▸ कृषि ▸ विश्लेषण ▸ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/-रू.

चैत्र-वैशाख 2079, अप्रैल 2022

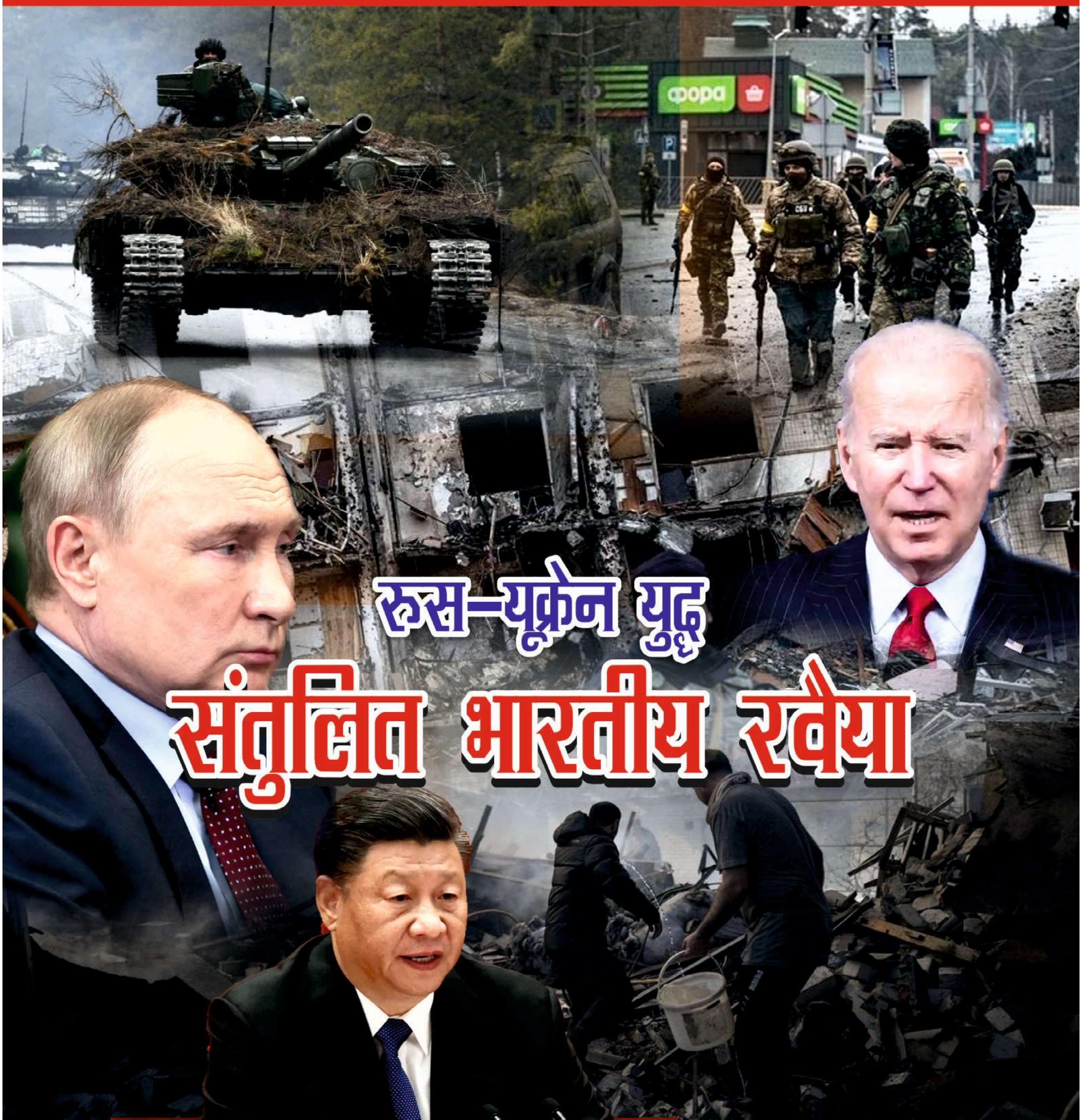

रूस-यूक्रेन युद्ध
संतुलित भारतीय रवैया

स्वदेशी पत्रिका और स्वदेशी परिवार की ओर से
स्वदेशी के सभी पाठकों, लेखकों तथा स्वदेशी में योगदानकर्त्ता को
विक्रम संवत् 2079
की
हार्दिक शुभकामनाएं
स्वदेशी पत्रिका
स्वायत्तता बनाम जिम्मेवारी
RESERVE BANK
Swadeshi
PATRIKA
SEPTEMBER 2018
Remembering Atal Ji,
The Consensus Builder
VOICE OF
SELF RELIANT INDIA
SWADESHI
Patrika
स्वदेशी
पत्रिका
पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

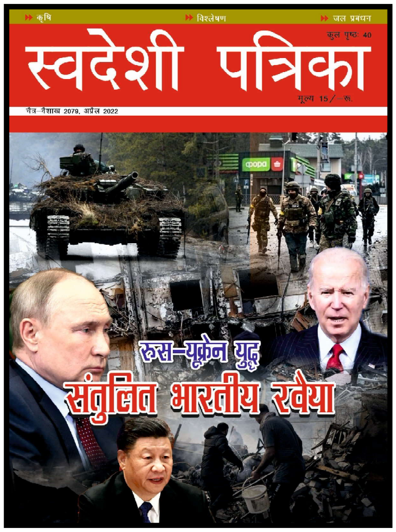

वर्ष–30, अंक–4

चैत्र–वैशाख 2079 अप्रैल 2022

संपादक

अजेय भारती

सह–संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–06

रूस–यूक्रेन युद्ध
संतुलित भारतीय रवैया

के.के. श्रीवास्तव

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

09 आवरण कथा
रूस–यूक्रेन संघर्षः भारत पर भी पड़ेगा व्यापक प्रभाव .... डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

11 विमर्श
अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आत्मनिर्भरता की दरकार .... डॉ. अश्वनी महाजन

13 आर्थिकी
कारोबार, चार सौ बिलियन के पार .... अनिल तिवारी

16 ऊर्जा
ऊर्जा का मूल्य बढ़ाइए, खपत घटाइए .... डॉ. भरत झुनझुनवाला

18 विश्लेषण
दिल्ली का बजटः झूठ की चासनी में जुमलों की सौगात .... विक्रम उपाध्याय

20 दृष्टिकोण
खुशी की गिनती में पीछे, पर खुशहाली में अव्वल है भारत .... अनिल जावलेकर

22 पहल
शिक्षा के भारतीयकरण की अनिवार्यता .... डॉ. जया कक्कड

25 विचार
भविष्य का ईंधन – हाइड्रोजन .... विनोद जौहरी

27 शिक्षा
चिकित्सा शिक्षा में आत्मनिर्भरता की दरकार .... स्वदेशी संवाद

29 रसोई
बढ़ रहा है मिलेट्स (सुपर फूड) का चलन .... शीला शर्मा

31 कृषि
समृद्ध खेती से ही पंजाब का स्थाई विकास .... देविन्दर शर्मा

33 पर्यावरण
पेड़ों के संरक्षण से ही सुधरेगा पर्यावरण .... राजेन्द्र शर्मा

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**

समाचार परिक्रमा **35-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

पाठकनामा

राज बदला, पर राग वही

कबीरदास की कमरी चढ़े न दूजो रंग। पाकिस्तान की सत्ता से इमरान खान की विदाई के बाद जिन लोगों के मन में कश्मीर को लेकर अच्छे–अच्छे सपने दिख रहे थे, उन्हें बामुलाहिजा होना चाहिए, क्योंकि जो नये आये है लगता है वो पहले से भी अधिक खार खाये है। सवाल है कि आखिरकार शाहबाज शरीफ को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि शपथ लेने से पहले ही कश्मीर को लेकर अति मुखर हो गये। दरअसल कश्मीर पर शाहबाज ने वही भाषा और उन्हीं शब्दों का इजहार किया है जो वहां की सेना उनके मुहं से सुनना चाहती है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि वहां की सेना के लिए कश्मीर कितना अहम मुद्दा है। अगर कश्मीर का मसला निकाल दिया जाए तो वहां की सेना के पास चौबीसों घंटे पहले गड्ढा खोदने और फिर उसे मुकम्मल भरने के अलावा आखिर काम ही क्या बचता है। कुछ छद्म युद्धों, सीमा पार से आतंकियों की खेप कहीं ओर पहुंचाने के अलावा पूरी पाकिस्तानी सेना का काम भारत और खासकर कश्मीर पर उल–जलूल करने के अलावा बचता ही क्या है? इसलिए नये साहिबान शाहबाज भी उसी रस्ते पर है जो उनके पूर्वजों के मूल्क की सियायसी परंपरा रही है।

इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री पद का पर्चा भरने के तत्काल बाद दी गई प्रतिक्रिया में शाहबाज ने कहा है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता, तब तक भारत के साथ रिश्ते सुधर नहीं सकते। इसमें ऐसी कौन सी बात है जिससे लगे कि वे बदलते हुए निजाम है। इस तरह की बातें वहां से नहाते खाते भी आती रही है। उल्लेखनीय यह है कि पाकिस्तान की सेना ने जिसे तरह बेआबरू कर इमरान को बाहर का दरवाजा दिखाया है, उससे कयास लगायी जा रही थी कि नये हुक्मरान के आने से वर्षों से जमी हुई रिश्तों की बर्फ कुछ पिघलेगी। पर यह ख्याली पुलाव था जो कुछ घंटे भी नहीं टिक सका। फौज को राजी करते हुए नये साहब ने जता दिया कि भारत या भारत के स्वर्ग कश्मीर को लेकर उनकी मंशा कबीरदास के उस कंबल के तरह की ही है जिस पर लाख कोशिश करें कोई और रंग चढ़ नहीं सकता।

डॉ. पराक्रम सिंह, धुंधरी, आजमगढ़, उ.प्र.

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

देश, विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं और जब संकल्पों के लिये दिन–रात ईमानदारी से प्रयास होता है, तो वे संकल्प, सिद्ध भी होते हैं।

नरेन्द्र मोदी,
प्रधानमंत्री, भारत

मेरा सपना दिल्ली और जयपुर के बीच एक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का है... एनएचएआई में सुधार की जरूरत है... निर्णय लेने में देरी उन चीजों में से एक है जहां हमें एनएचएआई में सुधार करने की जरूरत है।

नितिन गड़करी
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार

यह साफ हो चुका है कि भोजन को आधे से लेकर पांच सितारों की रेटिंग देने के मामले में एफएसएसएआई ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बड़े खिलाड़ियों की राय मान उपभोक्ता हितों की अनदेखी की है।

डॉ. अश्वनी महाजन
राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

हानिकारक पैक्ड खाने से लोगों को बचाने की दरकार

हाल ही में फूड एण्ड सेफ्टी सटैंडर्ड ऑथारिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई)ने खाने–पीने की वस्तुओं की पैकिंग के लेबल (एफओपीएल) के लिए खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के स्तर के बारे में लिखने की पद्धति पर चर्चा प्रारंभ की है। अब इस विषय पर एक बहस छिड़ गई है कि खाने के पैकेट पर भोजन की गुणवत्ता के बारे में 'स्वास्थ्य स्टार रेटिंग' दी जाए अथवा हानिकारक खाद्य के बारे में चेतावनी लिखी जाए। इस संबंध में एफएसएसएआई ने अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों यानि अल्ट्रा प्रोसेसड फूड इण्डस्ट्री के दबाव में यह निर्णय लिया है कि हर खाद्य पर एक से शुरू कर पांच सितारे तक रेटिंग की जाए। यह बात स्पष्ट हो गई है कि एफएसएसएआई ने यह निर्णय लेते हुए बड़े खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगों की राय को ज्यादा महत्व दिया है और उपभोक्ता हितों की अनदेखी की है।

हमारे देश में परंपरागत रूप से स्वास्थ्यप्रद खाना बनाने और खाने की परंपरा है। हमारे भोजन की थाली में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेड और अन्य पोषक तत्व अत्यंत संतुलित रूप में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा खानपान अत्यंत संतुलित रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का चलन बढ़ा है और खासतौर पर अतिप्रसंस्कृत यानि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य बड़े प्रमाण में बाजार में आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ कैंसर समेत अन्य कई बीमारियों का कारण बन रहे हैं। यही नहीं ग्राहकों को लुभाने और बच्चों को अपने उत्पादों की आदत या यूं कहें कि एडिक्शन करने के लिए कंपनियां चीनी, नमक (सोडियम) और वसा (फैट्स) का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। हमारे देश में लगातार बढ़ता मधुमेह का रोग, ब्लडप्रेशर, किडनी और लीवर की बीमारियां आदि खाने में चीनी, सोडियम और वसा के आधिक्य के कारण हो रही हैं। हमारे देश में पोषण के बारे में लोगों में जागरूकता कम होने के कारण और इस मामले में खाद्य पैकेटों पर कोई चेतावनी नहीं होने के कारण लोग अनजाने में इन हानिकारक खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसे कई बार लाइफ स्टाइल बीमारियां कहकर छोड़ दिया जाता है।

यदि ऐसे हानिकारक खाद्य पदार्थों पर, यह कहकर कि चेतावनी दर्ज की जाए कि इसमें एक सीमा से ज्यादा चीनी है, नमक है अथवा वसा है, तो उपभोक्ताओं को इनके दुष्प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी मिल पाएगी और वे अपने खानपान के बारे में जानकारीपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। यह सही है कि इन खाद्य पदार्थों को बनाने वाली कंपनियों को इस प्रावधान से नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे आमजन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकेगा। यह केवल सैद्धांतिक निष्कर्ष नहीं है, बल्कि अन्य देशों में ऐसा अनुभव भी किया गया है। चिली, ब्राजील, इजराइल सहित कई मुल्कों ने खाद्य पैकेटों पर इस प्रकार की चेतावनी अंकित करने का निर्णय किया। चिली ने तो इस संबंध में संबंध में कानून भी बनाया। कानून बनने के बाद वहां हानिकारक खाद्यों की बिक्री में भारी कमी आई। आज जब हम अपने देश में इस बारे में निर्णय कर रहे हैं तो हानिकारक खाद्यों के बारे में उपभोक्ताओं को चेतावनी देने की बजाय अस्वास्थ्यकारी खाद्यों को स्टार रेटिंग देकर उनको वैधता प्रदान करे, यह सही नहीं होगा।

इस बावत 15 फरवरी 2022 को आयोजित एफएसएसएआई द्वारा हितधारकों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों पर चर्चा करने की बजाय आईआईएम, अहमदाबाद और डेकस्टर कंस्लटेंसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन का हवाला दिया गया और यह बताया गया कि इस अध्ययन में लोगों ने यह राय दी है कि फूड पैकेट पर स्वास्थ्य स्टार रेटिंग की व्यवस्था को अपनाया जाए। गौरतलब है कि उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधियों ने और देश की सबसे बड़ी विज्ञान एवं पर्यावरण संस्था सेंटर फोर साइन्स एंड इन्वायरोन्मेंट के प्रतिनिधि ने इस निर्णय के खिलाफ अपना मत दिया। लेकिन उनके मत को दरकिनार कर यह कहा गया कि 20 हजार लोगों के सर्वे का महत्व ज्यादा है, इसलिए हितधारकों को हेल्थ स्टार रेटिंग पर ही अपना मत देना होगा। आईआईएम अहमदाबाद के सर्वेक्षण के अनुसार भी अवांछित पोषक तत्वों की अधिकता की उपस्थिति के चलते, खरीद के इरादे को कम करने के संदर्भ में चेतावनी का विकल्प बेहतर आंका गया है। लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट में पसंदीदा विकल्प के रूप में एचएसआर की सिफारिश, जो निष्पक्षता पर संदेह का कारण बन रही है। यही नहीं हितधारकों की बैठक, जिसमें हेल्थ स्टॉर रेटिंग के बारे में निर्णय हुआ, उसमें ना केवल बड़ी संख्या में कम्पनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे बल्कि विशेषज्ञों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कम्पनियों से सम्बद्ध हैं।

गौरतलब है कि आस्ट्रेलिया विश्व का मात्र एक देश है, जहां हेल्थ स्टार रेटिंग की व्यवस्था है, जबकि अधिकांश देशों में जहां एफओपीएल की व्यवस्था है, उसमें हेल्थ स्टार रेटिंग का नहीं बल्कि चेतावनी का प्रावधान है। किसी भी खाद्य पदार्थ की स्टार रेटिंग निश्चित करने के लिए एक लॉगरिथम या फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। मजेदार बात यह है कि इस फार्मूले को ग्रेग गैम्ब्रिल नाम के जिस व्यक्ति ने बनाया था, वो भी फूड इंडस्ट्री का ही हिस्सा था। इसलिए यह हितों के टकराव का मामला है। आस्ट्रेलिया के खाद्य वैज्ञानिकों में भी इसे लेकर चिंता है। इस फार्मूले के अनुसार किसी भी हानिकारक खाद्य पदार्थ में यदि कोई पोषक तत्व जैसे फल के जूस आदि मिला दिया जाए तो उसकी स्टार रेटिंग पाँच सितारे तक पहुँच सकती है। उदाहरण के लिए यदि अधिक चीनी वाले किसी पेय पदार्थ में संतरे का रस मिला दिया जाए, तो उसे कहीं अधिक स्टार मिल जाएंगे, और उपभोक्ता अनजाने में ही हानिकारक खाद्यों का सेवन करेगा, क्योंकि उसे यह जानने का अवसर नहीं मिलेगा कि वह एक हारिकारक खाद्य पदार्थ का उपभोग कर रहा है।

आज जब देश की खाद्य नियामक संस्था इस बावत निर्णय लेने जा रही है तो देश के लोगों की स्वास्थ्य रक्षा पहला उद्देश्य होना चाहिए, न कि कंपनियों के लाभ का। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह दायित्व है कि इन विषयों पर कड़ी नजर रखते हुए कंपनियों के दबाव में देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 'हेल्थ स्टार रेटिंग' की बजाय वो स्वास्थ्य के हानिकारक खाद्य पदार्थों के संबंध में 'स्पष्ट चेतावनी' का प्रावधान करे।

रूस-यूक्रेन युद्ध

संतुलित भारतीय रवैया

कहते हैं कि इतिहास अपने आपको दोहराता है। बदलती देशकाल परिस्थिति में वर्तमान की एकध्रुवीय दुनिया एक बार फिर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ऐतिहासिक विरासत की ओर बढ़ रही है। सवाल है कि बागडोर किसके हाथ में होगी? हाल के वर्षों में चीन की बढ़ती आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी ताकत के सामने क्या अमेरिका दुनिया की मुखतारी करने का जोखिम उठा सकता है? इस पर संदेह है, क्योंकि रोज–रोज आगे बढ़ते लंबे खींचते यूक्रेन युद्ध से रूस के साथ–साथ अमेरिका का रूतवा भी छलनी हुआ है। विश्व की अधिकांश शक्तियां इस पार या उस पार के खेमे में बट गई हैं। ऐसे में भारत संतुलित रवैया अपनाकर अशांत की दुनिया की धूरी और शांति की उम्मीदों का केंद्र बन गया है। भारत का किरदार अहम हो गया है। मानवता को विनाश से बचाने के लिए दुनिया का हर देश आज भारत की ओर देख रहा है। खासकर इस संकट को लेकर भारत जिस तरह अमेरिकी दबाव को भी दरकिनार कर खुद अपने लिए हितकारी जिस स्वतंत्र नीति पर अटल खड़ा है, उसने बाकी दुनिया को भी प्रेरित किया है। पूरे घटनाक्रम में भारत ने न तो रूसी हमले की निंदा की है और न ही रूस से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की किसी वोटिंग में हिस्सा लिया है, लेकिन साथ ही यह भी लगातार कहता रहा है कि कूटनीति का रास्ता अपनाकर युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। यही नहीं भारत ने यूक्रेन को मानवीय मदद भी भेजी है। इन सबके बीच रूस पर अमेरिका के 5000 से ज्यादा छोटे बड़े प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से किफायती दामों पर कच्चे तेल का करार भी किया है, वह भी डालर के बदले रूबल में। हालांकि भारत का यह कदम अमेरिकी कूटनीति के लिए बड़ा झटका है लेकिन भारत अपने नागरिकों के हितों के सापेक्ष संतुलन बनाकर चलने की नीति पर आगे बढ़ रहा है।

भारत का अब तक का स्टैंड सभी हितधारकों के हितों का त्याग किये बिना अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य करने की परीक्षा में अब तक सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुआ है। आशा की जानी चाहिए कि आगे भी यह तासीर कायम रहेगी।

– केके श्रीवास्तव

इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन के युद्ध ने वैश्विक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त कर दिया है। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने दुश्मन के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा कर दी है। यह प्रतिबंध न केवल रूस बल्कि भारत सहित अन्य देशों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। तेल के साथ–साथ आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। भुगतान चैनल बाधित हो गए हैं। भोजन की कमी और मुद्रास्फीति के दबाव की गिरफ्त में धीरे–धीरे दुनिया के हर देश आ रहे हैं। पश्चिमी देश रूस के खिलाफ वित्त और व्यापार प्रणाली को हथियार बनाए हुए हैं, लेकिन भारत ने अपनी संतुलित कूटनीति से सबके साथ संबंधों में मानवीय पुट बनाए रखा है।

आयातित ऊर्जा पर 70 प्रतिशत निर्भरता के साथ भारत एक निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। बढ़ती ऊर्जा की कीमतें हमारे लिए दुष्कर है, क्योंकि कोविड–19 के दौरान देश में मुद्रास्फीति की दर 12 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। सरकार ईंधन करों को कम करने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि यह हमारे वित्तीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ऐसी स्थिति में अगर भारत रियायती मूल्य पर तेल की आपूर्ति के रूसी प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो इसमें दोष नहीं दिया जा सकता है।

यूक्रेनियन संघर्ष, सोवियत संघ के पतन, यूरोप में न्याय संगत सुरक्षा, स्थापित करने में विफलता, पूर्व की ओर नाटो के विस्तार और दोनों देश के बीच किसी भी रचनात्मक वार्ता के टूटने के साथ–साथ यूएस व रूसी संबंधों के लगातार गिरावट का एक उत्पाद है। रूस को तब उकसाया गया जब अमेरिका ने यूक्रेन और जॉर्जिया को कवर करने के लिए नाटो का विस्तार करने की मांग की। रूस ने इसे तत्काल खतरा तथा अस्तित्व का संकट करार दिया। हालांकि सैद्धांतिक रूप से भारत को यूक्रेन पर आक्रमण का विरोध करना चाहिए था, पर वास्तविक और व्यावहारिक राजनीति यही कहती है कि भारत को रूस से रक्षा संबंधों सहित अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करनी चाहिए। क्या भारत पश्चिमी देशों की उस चुप्पी को भूल जाए, जब चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था।

यूक्रेनियन संघर्ष, सोवियत संघ के पतन, यूरोप में न्याय संगत सुरक्षा, स्थापित करने में विफलता, पूर्व की ओर नाटो के विस्तार और दोनों देश के बीच किसी भी रचनात्मक वार्ता के टूटने के साथ-साथ यूएस व रूसी संबंधों के लगातार गिरावट का एक उत्पाद है।

निश्चित रूप से अगर भारत को एक तरफ अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले अमूर्त और अलग–अलग सिद्धांतों का पालन करने तथा दूसरी तरफ अपने हितों की रक्षा करने के बीच चयन करना है तो विवेक की मांग है कि हम दूसरे की और झुके। इस तरह तार्किक रूप से भी भारत को बिना किसी भय के अमेरिका सहित पश्चिम की नैतिक भव्यता और परोक्ष चेतावनियों की अनदेखी करनी ही चाहिए। ऐसा हो सकता है कि चीनी आक्रमण की स्थिति में रूस भारत का पक्ष न ले क्योंकि यह 'चीन–रूस की कोई सीमा नहीं', मित्रता में कनिष्ठ साझेदार हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि विदेश नीति की आपनी अनिवार्यताए हैं, विचलन के बिंदु तो बने रहेंगे। चीन और रूस के संबंध अमेरिका के प्रति साझा शत्रुता पर आधारित है।

उल्लेखनीय तथ्य है कि पिछले दो दशकों में जहां अमेरिका के साथ भारत के सामरिक और आर्थिक संबंध गहरे हुए हैं उसी समय काल में चीनी साम्राज्य के साथ हमारे संबंध बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं और अमेरिका के वे दिन लद गए जब पूरी दुनिया पर एक तरह से उनका बोलबाला था।

वित्तीय और व्यापार प्रतिबंधों के कारण रूस निश्चित रूप से कम शक्ति के साथ एक सिकुडती अर्थव्यवस्था के रूप में रह जाएगा, लेकिन भारत यूरोपीय देशों द्वारा प्रतिबंध के बावजूद

रूस से आयात करने के पाखंड को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। चीन के लगातार विस्तार के कारण दुनिया तेजी से बदल रही है। डालर का प्रभुत्व खतरे में है। राष्ट्र अपने स्वयं के डिजिटल आर्किटेक्चर का निर्माण कर रहे हैं और स्विफ्ट जैसे वित्तीय प्लेटफार्म सहित पश्चिम आधारित संस्थानों को तिरस्कार के साथ देखा जा रहा है। ऐसे में भारत को अपनी ऊर्जा और सैन्य जरूरतों को देखते हुए पुरानी दोस्ती का त्याग किए बगैर नई दोस्ती की खेती हेतु एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। भारत को आत्म संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे अपनी आंतरिक नियमों और आयोजनों को लगातार जांचना चाहिए, अपनी बाहरी पहुंच को बनाए रखना चाहिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी क्षमताओं के अनुरूप आगे कार्य व्यवहार करना चाहिए। एक सच्ची रणनीतिक साझेदारी मूल हितों की पारस्परिकता पर आधारित होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम से परहेज हमारे हितों पर प्रभाव नहीं डालते, लेकिन रूस के खिलाफ मतदान करना हमारे लिए संकट का सबब बन सकता है। इसलिए भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए हिंसा की पूर्ण समाप्ति, बातचीत के माध्यम से मतभेदों का समाधान और राष्ट्र राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की मान्यता और संरक्षण का बार–बार आवाज उठाना एक बेहतर कदम है।

लेकिन साथ ही साथ हमें 1991 के बाद से भारत के आर्थिक सुधारों और अंततः अमेरिका भारत परमाणु समझौते के लिए अमेरिका के मजबूत समर्थन को भी नहीं भूलना चाहिए। हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का नेतृत्व किया है तथा अमेरिका के साथ हमारे संबंधों की कसौटी यूक्रेन पर हमारे द्वारा लिए गए रूप से कहीं अधिक व्यापक होनी चाहिए।

भारत को अपने संतुलनकारी नीतियों के साथ बने रहने की जरूरत है। भारत रूस संबंध एक बहुत ही तरल भू–राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकते हैं। भारत ने रूसी आक्रमण के खिलाफ अब तक तटस्थ रूख अपनाया है, लेकिन इसे लगातार मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या और विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय हित की गणना के संदर्भ में निरंतर तटस्थता लाभकारी होगी? भारत को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत–रूसी सैन्य सामानों का सबसे बड़े खरीददार के रूप में है। सैद्धांतिक रूप से चाहे बातें जो भी हैं। रूस हथियारों की आपूर्ति को कम करने का जोखिम नहीं उठा सकता है क्योंकि हालिया प्रतिबंधों को देखते हुए रूस को भारतीय धन की और अधिक जरूरत है। इसलिए भी भारत को रूस और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी के बीच एक बेहतर संतुलन की जरूरत है क्योंकि भारत अमेरिका से भी एकबारगी अलग नहीं हो सकता।

अमेरिका बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अन्य देशों की तुलना में भारतीय कंपनियों का और बैंकों का एक्सपोजर अमेरिका में अधिक है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की अमेरिका में अच्छी पहुंच है। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर छात्र समुदाय भी अमेरिका में मौजूद हैं। आज की तारीख में भारत को अमेरिका की जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत अमेरिका को भारत की भी है। बीजिंग की हालिया तेजी को ब्रेक देने के लिए क्वाड का गठन किया गया है।

बहरहाल भारत का अब तक का स्टैंड सभी हितधारकों के हितों का त्याग किये बिना अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य करने की परीक्षा में अब तक सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुआ है। आशा की जानी चाहिए कि आगे भी यह तासीर कायम रहेगी। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

रूस-यूक्रेन संघर्ष

भारत पर भी पड़ेगा व्यापक प्रभाव

रूस ने अपने पड़ोसी देश युक्रेन पर 23 फरवरी 2022 को आक्रमण कर दिया। यह युद्ध यूक्रेन की धरती पर लड़ा जा रहा है जिसका यूक्रेन के साथ–साथ संपूर्ण विश्व पर आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। 25 दिसंबर 1991 को रूस के 15 टुकड़े हुए थे। रुस के उन टुकड़ों में यूक्रेन भी एक देश बन गया था। भारत की अर्थव्यवस्था अभी मार्च 2022 को समाप्त दो वर्ष में कोरोना की विभीषिका से ठीक प्रकार से निकली भी नहीं है। भारत को रुस, अमेरिका व चीन के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होगी हालांकि भारत ने स्वयं को इस युद्ध में तटस्थ बने रहने की रीति नीति अपनाई है परंतु भारत पर आर्थिक ज्यादा व राजनीतिक भी थोड़े बहुत प्रभाव पड़ेगा ही।

रूस ने यूक्रेन पर एकदम से आक्रमण नहीं किया। कुछ वर्षों से दोनों देशों के बीच तनातनी चली आ रही थी। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर एक लाख से अधिक सैनिक तैनात किए हुए थे। मौजूदा तनाव व टकराव वर्ष 2013 में बन गया था जब यूक्रेन में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय यूनियन से चल रही महत्वपूर्ण राजनीतिक व व्यवसायिक ड़ील रोक दी थी जिसके विरोध में यूक्रेन में हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। मार्च 2014 में रूस ने क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया तथा कुछ समय बाद ही रूस ने यूक्रेन के आंशिक क्षेत्र डोनत्सक तथा लुहांस्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इन दोनों क्षेत्रों में रूस समर्थकों की संख्या अधिक थी जिससे टकराव और बढ़ गया। मार्च 2014 से अब तक तीन हजार के लगभग नागरिकों की मौत हो चुकी है। हथियार, प्रशिक्षण एवं सैन्य के रूप में यूक्रेन को नाटो से मिलने वाले सहयोग को रूस अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन यह गारंटी दे कि वह नाटो का सदस्य नहीं बनेगा और नाटो रूस की तरफ अपना विस्तार नहीं करेगा। पुतिन नहीं चाहते कि यूक्रेन में नाटो का मिसाइल सिस्टम तैनात किया जाए। रुस पड़ोस में दुश्मन नहीं चाहता तथा अमेरिका नाटो व यूक्रेन के मामलों में अपना दृष्टिकोण बदलें जिससे रूस की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो सके।

रुस व यूक्रेन को बातचीत की मेज पर आना चाहिए क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। युद्ध के दुष्परिणामों का दुष्प्रभाव दोनों देशों की जनता के साथ साथ सम्पूर्ण विश्व के लोगों को भी भुगतना पड़ता है।

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

यूक्रेन का मानना है कि यदि वह नाटो के साथ संबंध बढ़ाता है तो इसमें रूस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नाटो से जुड़ना अथवा नहीं जुड़ना यह उसके अधिकार क्षेत्र में हैं। यूक्रेन को नाटो का सदस्य न बनने की गारंण्टी पूरी तरह से अवैधानिक है। यूक्रेन का मानना है कि रूस यूक्रेन में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहता है। यूक्रेन ऊर्जा संकट के साथ साथ अनेक घरेलू राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। नाटो का मानना है कि यूक्रेन के पास नाटो का सदस्य बनने का विकल्प हर समय खुला हुआ है। नाटो रुस पर आर्थिक, वित्तीय व राजनीतिक प्रतिबंध लगा सकता है।

यूक्रेन संकट का भारत पर प्रभाव

क्रूड़ तेल के उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत है। यह ओपेक के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत है। पश्चिमी यूरोप के देश प्राकृतिक गैस के लिए रूस पर बहुत कुछ निर्भर है। यदि यह आपूर्ति बाधित होती है तो तेल के मूल्य बढ़ने से वैश्विक स्तर पर महंगाई भी बढ़ेगी जिससे भारत में पेट्रोल व डीजल के दाम भी बढ़ेंगे जिससे भारत में महंगाई भी बढ़ सकती है। भारत के सैन्य उत्पादन के आयात में रूस की बड़ी भागिता है। भारत को रूस के अलावा दूसरा विकल्प भी सोचना व खोजना पड़ेगा।

सोवियत संघ के विघटन से पूर्व अर्थात 25 दिसंबर 1991 से पूर्व भारत के निर्यात में रुस की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत थी जो विघटन के उपरान्त एक प्रतिशत ही रह गई। आयात में भी रूस की हिस्सेदारी 1.40 प्रतिशत है। रूस के आक्रमण का भारत के विदेश व्यापार पर ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव उन कोशिशों पर पड़ेगा जो भारत रूस को अधिक उत्पादन निर्यात करने के लिए कर रहा है। भारत के हथियार आयात में रूस का हिस्सा 49 प्रतिशत है। रूस के हथियार निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत है।

वैश्वीकरण के मजबूत जाल में विश्व के देश अब किसी भी देश में जरा सी प्रतिकूल स्थिति से अछूते नहीं रहते हैं भले ही उनके बीच द्विपक्षी संबंध बहुत गहरे न हो। भारत सरकार खाद्य तेल से लेकर खाद तक के कारोबार का मूल्यांकन कर रही है। भारत सरकार कृषि उत्पादन और फार्मा के निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित है तथा संकट के कारण निर्यातकों के भुगतान को लेकर होने वाली परेशानियों का भी मूल्यांकन किया जा रहा है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार सरकार उन वस्तुओं को लेकर चिंतित है जिनकी आपूर्ति यूक्रेन से होती है। खाद्य तेल की आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कृषि निर्यात के लिए भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। भारत को सूरजमुखी तेल के आयात में 74 प्रतिषत हिस्सेदारी यूक्रेन की है जिसकी आपूर्ति बाधित हो चुकी है। इसका प्रभाव पाम ऑयल के आयात पर पड़ेगा जिससे देश में खाद्य तेल की कीमतें भविष्य में बढ़ सकती है। भारत से फार्मा के निर्यात पर भी असर पड़ेगा।

भारत रूस को 200 करोड़ डॉलर अर्थात लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। यूक्रेन को 50 करोड़ डॉलर अर्थात लगभग 3,750 करोड रुपए का ही निर्यात करता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि वैश्विक रूप से नकारात्मक माहौल बन रहा है। भारत का वार्षिक तेल आयात 7.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ कर 9.50 लाख करोड़ रुपये का हो चुका है जो कि देश के कुल आयात का 20 प्रतिशत है। भारत का भुगतान संतुलन गड़बड़ा जाएगा। भारत में विदेशी मुद्रा का एक मजबूत भंड़ार है। परन्तु फिर भी विदेश व्यापार पर अनिश्चितता के बादल छा गये है।

अमेरिका यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने को तैयार है तथा उसको सैन्य सामग्री प्रदान कर रहा है। अमेरिका अपने हितों को लेकर विश्व व्यवस्था के लिए चीन के आक्रमक उभार को लेकर चिंतित है। वह रूस को घेरने में लगा हुआ है। वह इससे यूक्रेन संकट को और उलझा रहा है तथा रुस को चीन के पाले में धकेलने का काम कर रहा है। अमेरिका को चीन पर लगाम लगाने पर ध्यान देना चाहिए परंतु वह रूस के रूप में उसे एक सहयोगी उपलब्ध करा रहा है।

रूस को यूक्रेन में अलगाववाद को पनपाना नहीं चाहिए। इस प्रतिकूल प्रभाव का विश्व के अनेक हिस्सों पर भी पड़ेगा। रूस यूक्रेन के मामले में भारत किसी पाले में नहीं खड़ा है। वह संकट को सुलझाने में तटस्थ रहकर सहयोग दे रहा है। भारत को भी संकट से सीख लेते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के समस्त उपाय करने चाहिए क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से ही भारत के 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक की रकम स्वच्छ ऊर्जा के विकास पर लगेगी जिससे भारत में रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे तथा अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो सकेगा तथा देश का बजट तेल की कीमतों का बंधक नहीं बन सकेगा। भारत में महंगाई बढ़ने से राजनीतिक संकट गहरा हो सकता है।

यह युद्ध तभी बंद हो सकता है जब यूक्रेन इस बात की गारंटी देगा कि वह नाटो का सदस्य नहीं बनेगा तथा अमेरिका रूस की सीमाओं के पास से अपने सैनिक और हथियार वापस बुला लेगा। रूस ने युद्ध से पूर्व लिखित प्रस्ताव भी दिया था परंतु कोई सार्थक जवाब उसको नहीं मिला था। रुस व यूक्रेन को बातचीत की मेज पर आना चाहिए क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। युद्ध के दुष्परिणामों का दुष्प्रभाव दोनों देशों की जनता के साथ साथ सम्पूर्ण विश्व के लोगों को भी भुगतना पड़ता है।❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आत्मनिर्भरता की दरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता ही सबसे उपयुक्त रणनीति है। कुछ लोगों का मानना है कि यदि यह युद्ध इसी प्रकार से चला और यूक्रेन के मित्र देश जैसे अमरीका और यूरोपीय देश इस युद्ध में कूदे तो यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा सकता है। लेकिन इस चिंता के अलावा भारत और शेष दुनिया में कुछ अन्य प्रकार की चिंताएं व्याप्त हैं। इन्हीं चिंताओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की रणनीति का आह्वान किया है।

महंगाई

गौरतलब है कि रूस दुनिया के कच्चे तेल उत्पादकों में तीसरे स्थान पर है। अमरीका और उसके अन्य मित्र देशों द्वारा रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के चलते कच्चे पेट्रोलियम तेल की आपूर्ति अवरूद्ध हो रही है। इस कारण दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अभी तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव चल रहा है, लेकिन इस बीच रूस ने भारत को बाजार से 25 प्रतिशत कम कीमत पर तेल की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है। भारत ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और कुछ मात्रा में रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल आयात होने भी लगा है। लेकिन रूस से तेल आयात करने की राह आसान नहीं है। हालांकि अमरीका ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सख्त रूख अपनाया हुआ है, लेकिन उसने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने से उसके प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं होगा। इसके बावजूद हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत द्वारा सस्ते कच्चे तेल के आयात में कोई बाधा न आए, ताकि देश को महंगाई से बचाया जा सके।

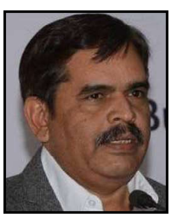

हम अपनी भुगतान प्रणाली और विभिन्न देशों की भुगतान प्रणाली के बीच श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं, और अमरीका और यूरोपीय देशों के अधीन चलने वाली स्वीफ्ट प्रणाली को धत्ता दिखा सकते हैं।

– डॉ. अश्वनी महाजन

अवरुद्ध भुगतान

दुनिया के लेनदेन में इस्तेमाल होने वाली 'स्विफ़्ट' व्यवस्था से अमरीका और यूरोपीय देशों ने रूस के बैंकों को ब्लॉक कर दिया है। इस समस्या का समाधान खोजते हुए भारत और रूस ने यह फैसला किया है कि रूस के साथ अब व्यापार रूपए और रूबल में होगा, यानि भारत न केवल 25 प्रतिशत सस्ता तेल खरीदेगा, बल्कि उस तेल का भुगतान भी रूपयों में किया जाएगा।

सवाल यह है कि स्विफ़्ट को ब्लॉक करने का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? स्विफ़्ट के ब्लॉक होने से भारत और दुनिया को भुगतान की वैकल्पिक व्यवस्थाएं निर्मित करनी होंगी। चीन की भुगतान प्रणाली जिसे क्रास बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम (सीआईपीएस) कहते हैं, उसके माध्यम से भी भुगतान संभव है, तो भी भारत और रूस ने रूपए–रूबल में भुगतान करने का निर्णय किया है। उधर भारत के बैंक हालांकि चीन की भुगतान प्रणाली सीआईपीएस में पंजीकरण करके रूस के साथ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सीआईपीएस युआन यानि आरएमबी को कैरेंसी के नाते उपयोग करता है, भारत के लिए अच्छा यह होगा कि वो एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली तैयार करे जो भारतीय रूपए पर आधारित हो।

वैकल्पिक व्यवस्था में एक विकल्प यह है कि भारत अपनी यूपीआई की भुगतान प्रणाली को रूस की मीर प्रणाली से संबद्ध करे ताकि आसानी से भुगतान किया जा सके। इसके अलावा दूसरा विकल्प यह है कि केन्द्रीय बैंक की डिजिटल कैरेंसी के माध्यम से भुगतान हो सके, इसके लिए रूस के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपना खाता खोल सकते हैं और जहां रूसी बैंक भारतीय रूपए का जमा रख सकते हैं। लेकिन यहां मुश्किल यह आ सकती है कि चूंकि भारत और रूस के व्यापार में भारत को व्यापार घाटा है, इसलिए रूस के पास भारतीय रूपयों की जमा बढ़ जाएगी। ऐसे में रूस अन्य देशों, जो रूपए में भुगतान स्वीकार करते हैं, से आने वाले आयातों के लिए रूपयों में भुगतान कर सकता है।

भरोसा टूटा

विभिन्न देशों के केन्द्रीय बैंक दूसरे मुल्कों में विदेशी मुद्रा रखते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अमरीका के केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्व) में अपनी विदेशी मुद्रा रखी हुई है, उसी प्रकार अन्य देशों ने भी डालरों के भंडार फेडरल रिजर्व में रखे हुए हैं, जिसमें रूस भी शामिल है। अमरीका और यूरोपीय देशों द्वारा रूस के बैंकों को स्विफ्ट में ब्लॉक करने के कारण रूस के विदेशी मुद्रा भंडारों पर अब रूस की पहुंच समाप्त हो गई है। ऐसे में रूस का तो अमरीकी फेडरल रिजर्व पर भरोसा उठा ही है, दुनिया के दूसरे मुल्क भी अब यह सोचने लगे हैं कि उनकी दूसरे केन्द्रीय बैंकों में जमा राशि सुरक्षित नहीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि रूस, अमरीका और उसके मित्र देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण मुश्किल में है, भारत के लिए तुरंत तो कोई खतरा नहीं, लेकिन चूंकि भारत पर अमरीका पहले भी आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है, हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर ने भी यह कहा है कि चाहे भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगने की संभावनाएं नहीं हैं तो भी मुझे लगता है कि सभी देशों को अब अपने विदेशी मुद्रा भंडारों के बारे में विचार ज़रूर करना चाहिए। भारत ने पहले ही अपने विदेशी मुद्रा भंडारों को विस्तारित करना प्रारम्भ कर दिया है और आज हम अपने भंडारों को स्वर्ण, डॉलर, यूरो समेत कई अन्य कैरेंसियों में रख रहे हैं।

चूंकि दुनिया के व्यापार में डॉलरों का प्रभुत्व है और अमरीकी बैंकों में ही डॉलर रखे जाते हैं, क्योंकि किसी भी देश की संप्रभु कैरेंसी उसी देश के बैंकों में ही रखी जा सकती है। जैसे यूरो यूरोपीय बैंकों में, डॉलर अमरीकी बैंकों में, युआन चीनी बैंकों में और भारतीय रूपया भारतीय बैंकों में ही रखा जा सकता है। और आपसी लेनदेन के लिए नॉस्ट्रो एकाउंट खुलता है, जिसका स्वामित्व दूसरे देश के नागरिक के पास हो सकता है। भारत के लिए यही उपयोगी होगा कि भारत का अपनी ही भुगतान प्रणाली हो जो रूपए पर आधारित हो।

आत्मनिर्भर भुगतान प्रणाली

ऐसे देश जिन पर अमरीका, यूरोपीय देशों और उनके सहयोगियों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, उनको अपने सामान का किसी न किसी प्रकार से बेचना जरूरी है और इसलिए वे भारत को बाजार से सस्ता सामान बेचने के लिए तैयार हैं। युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन रूस ही नहीं बल्कि ईरान भी तेल को सस्ते दामों में और हमारी शर्तों (रूपए में भुगतान के बदले) पर बेचने के लिए तैयार है। ऐसे देशों से तो हम वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत अपनी–अपनी कैरेंसियों में भुगतान कर सकते हैं। लेकिन कई मुल्कों के साथ हमारा व्यापार घाटा रहता है, इसलिए वस्तु विनिमय हमेशा व्यवहारिक नहीं है।

ऐसे में हम अपनी भुगतान प्रणाली और विभिन्न देशों की भुगतान प्रणाली के बीच श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं, और अमरीका और यूरोपीय देशों के अधीन चलने वाली स्वीफ्ट प्रणाली को धत्ता दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत, रूस की मीर भुगतान प्रणाली, चीन की भुगतान प्रणाली समेत अन्य देशों की भुगतान प्रणाली के बीच श्रृंखला स्थापित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में आत्मनिर्भरता स्थापित कर सकते हैं।

यही नहीं, आजकल डिजिटल कैरेंसी का चलन बढ़ गया है, प्राइवेट क्रिप्टो कैरेंसियों के मूल्य में भारी उतार–चढ़ाव के चलते उनको तो भुगतानों के लिए इस्तेमाल करना खतरनाक होगा, लेकिन भारत ने हाल ही में अपने केन्द्रीय बैंक यानि भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से एक डिजिटल कैरेंसी जारी करने का निर्णय लिया है। जानकारों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस डिजिटल कैरेंसी के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संभव हो सकता है।

आज जब भारत प्रतिरक्षा के साजोसामान, इलैक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, रसायन, उपभोक्ता वस्तुएं आदि सभी में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की दृष्टि से हम अमरीका और यूरोप जैसे देशों की मनमर्जी के अधीन न रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम येन–केन–प्रकारेण अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के संदर्भ में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। प्रक्रिया कोई भी अपनाई जाए चाहे वस्तु विनिमय या विभिन्न भुगतान प्रणालियों के बीच श्रृंखला निर्माण अथवा डिजिटल कैरेंसी, सभी के पीछे आत्मनिर्भरता का भाव है। ❑❑

कारोबार, चार सौ बिलियन डालर के पार

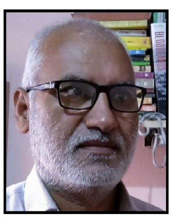

दुनिया का हर देश भारत की ओर ललचाई नजर से देख रहा है। हर कोई चाहता है कि इस संकट काल में भारत उसके साथ रहे। स्वास्थ्य आपदा के दौरान जिस तरह तमाम देशों को वैक्सीन और दवाई पहुंचाई गई उससे भारत की अहमियत विश्व भर में बढ़ी है।

– अनिल तिवारी

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वर्ष 2021–22 में पहली बार भारत का निर्यात 400 बिलियन डालर पर पहुंच गया है। इससे पहले यह सबसे अधिक वर्ष 2018–19 में 330 बिलियन डालर के आंकड़े के पास था। कोरोना महामारी के दौर में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई है। कोरोना संकट के रूप में मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आपदा से दुनिया अभी ठीक से उबर नहीं पाई थी कि यूक्रेन के बहाने आ पड़ी युद्ध आपदा ने दुनिया भर के देशों की बची खुची अर्थव्यवस्था की चूलें हिला कर रख दी है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस उपलब्धि के मायने क्या है?

सबसे पहले उन क्षेत्रों पर गौर करते हैं, जिनके अच्छे प्रदर्शन से भारत निर्यात में इस रिकार्ड ऊंचाई को हासिल कर सका है। मोटे तौर पर इंजीनियरिंग उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद और हीरा जवाहरात आभूषण का निर्यात बीते वर्ष भारत में कुल निर्यात में दो तिहाई रहा। ऑर्गेनिक ओर इनॉर्गेनिक केमिकल्स कोटन यानि हैंडलूम उत्पाद आदि इलेक्ट्रिक सामान, प्लास्टिक और लिमोनियम सामुद्रिक उत्पाद आदि ऐसे आइटम रहे जिसने भारत की निर्यात बास्केट में खासी जगह पाई है।

अब यहां से यह सवाल उठता है कि क्या निर्यात में बढ़ोतरी का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जैसे की जीडीपी के आंकड़ों के मामले में होता है। ठीक उसी तरह हमें निर्यात संबंधी आंकड़े को लेकर दो बातें ध्यान में रखनी होगी। पहला, चूंकि यह आंकड़े पारिभाषिक होते हैं इसलिए वैश्विक बाजार में वस्तुओं के मूल्यों के उतार–चढ़ाव के चलते इनमें भी उतार–चढ़ाव संभव है। दूसरा, विश्व बाजार के घटनाक्रम का किसी भी देश के निर्यात पर असर पड़ना अवश्यम्भावी है। भारत का निर्यात इन दोनों कारणों से लाभान्वित हुआ है। बीते वर्ष विश्व बाजार में वस्तुओं के दामों में वृद्धि का रुझान रहा। जिससे भारत के निर्यात का मूल्य बढ़ा खासकर पेट्रोलियम उत्पादों और धातुओं के दामों में यह रुझान देखने को मिला। अलबत्ता वैश्विक मुद्रा स्थिति का भारतीय निर्यात पर असर नहीं आंका जा सका है, जिसके लिए निर्यात की मात्रा और मूल्य संबंधी अंतिम आंकड़े आने के बाद ही आकलन लगाया जा सकेगा।

बहरहाल वैश्विक मुद्रास्फीति आंकड़े बढ़ते भी हैं तो भारत का निर्यात अपनी बढ़त बनाए रखेगा। बेशक बीते साल में महामारी संबंधी प्रतिबंध खत्म किए जाने, वस्तुओं के दामों में बढ़ने के रुझान, प्रोत्साहन पैकेजओं के जरिए मांग पैदा करने के प्रयासों से भारतीय उत्पादों की मांग में इजाफा हुआ और इजाफे की धारणा भी मजबूत हुई, जिसका फायदा निश्चित ही भारत को निर्यात के मोर्चे पर मिला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने की सराहना करते हुए कहा है कि यह आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में मील का पत्थर है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा "भारत 400 अरब डॉलर की वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य रखा था इसे हासिल कर लिया गया है। पहली बार इतना ऊंचा लक्ष्य हासिल किया गया है। मैं अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं, निर्यातकों को इस सफलता की बधाई देता हूं। यह आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में मील का पत्थर है।" खुद प्रधानमंत्री द्वारा देश के किसानों, बुनकरों, लघु उद्योगों की भूमिका को रेखांकित किया जाना, अपने आप में एक बड़े महत्व का विषय है। यहां उल्लेखनीय है कि भारत को निर्यात का यह मुकाम पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग, रत्न एवं आभूषण और रसायन जैसे क्षेत्रों की बदौलत हासिल हुआ है। यानि कि 400 अरब डालर के आंकड़े में साज सामान का निर्यात प्रमुख है। सॉफ्टवेयर का निर्यात इसमें शामिल नहीं है। सॉफ्टवेयर के निर्यात की गणना अलग से होती है।

भारतीय साजोसामान के निर्यात में बढ़ोतरी एक तरह से भारत के पद, प्रतिष्ठा और साख की बढ़ोतरी है। इंजीनियरिंग, रासायनिक उत्पादों के मामले में अगर निर्यात उपलब्धियों को देखा जाए तो एक हद तक यह मेक इन इंडिया की कामयाबी की कहानी ही कहता है। भारत में बनने वाले साजोंसामान को अगर बेहतर निर्यात के लिए बाजार मिलता है तो इसका मतलब है कि भारत में बनने वाले साजों सामान की स्वीकार्यता एवं उसकी गुणवत्ता लगातार बढ़ रही है। थोड़ा और आगे बढ़कर देखें तो भारत के साजोंसामान की पहुंच बढ़ते हुए दुनिया भर में फैलती है तो इसका सीधा लाभ मध्यम, लघु और छोटे कारोबारियों को मिलेगा। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर के निर्यात से बड़ी कंपनियों को फायदा मिलता है तो उसका असल फायदा बहुत पढ़े–लिखे कुशल कर्मियों के पक्ष में जाता है। वहीं अगर उदाहरण के लिए मुरादाबाद से पीतल की कलाकृतियों का निर्यात बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि इसका लाभ छोटे कारीगर को बहुत अधिक मिल सकेगा जो कि समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सुखद होगा।

कोरोना आपदा के चलते आज से लगभग दो साल पहले देश में लॉकडाउन लगाया गया था। जनजीवन लगभग ठहर गया था। लोग घरों में कैद थे और आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई। शेयर बाजार, रियल स्टेट, मैन्युफैक्चरिंग जैसे तमाम क्षेत्रों में मंदी का माहौल पसर गया। महंगाई और बेरोजगारी लगातार ऊंचाई हासिल करने लगी। यही वह आपदा काल था जो देशवासियों के जीवट का नजीर बन गया है अवसर मिलते ही देश ने उम्मीद से बढ़कर बेहतर प्रदर्शन किया। जिसका परिणाम है कि बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था जल्दी से पटरी की ओर लौट पड़ी और निर्यात का आंकड़ा आज एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। अप्रैल–जून 2020 में जीडीपी जहां घटकर –24.4 प्रतिशत हो गई थी, वही अक्टूबर दिसंबर 2021 में यह 5.4 प्रतिशत पर पहुंच गई। 23 मार्च 2020 को सेंसेक्स 25981 पर था जो अक्टूबर 2021 में 62345 के रिकॉर्ड पर बंद हुआ। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस क्षेत्र में जोरदार रिकवरी हुई है। रियल स्टेट भी उत्साहवर्धक है। ऑटो सेक्टर के भी दिन लौट आए हैं। बेरोजगारी के मामले में भी स्थिति पहले से बेहतर हुई है। बेरोजगारी की दर अप्रैल 2020 में 23.52 प्रतिशत थी जो मई 2021 में यह 11.84 प्रतिशत और फरवरी 2022 आते–आते गिरकर 8.1 प्रतिशत ही रह गई है। महंगाई के मोर्चे पर भी सुधार जारी है। अक्टूबर 2020 में महंगाई की दर 7.6 प्रतिशत थी जो कि फरवरी 2022 में 6.01 प्रशित दर्ज की गई।

हालांकि रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल कर कोरोना की काली साया से बाहर निकल रही दुनिया की जान फिर से सांसत में डाल दी है। तमाम देश खेमों में बंट गए हैं और युद्ध के बाद की कल्पना कर सिहर रहे हैं। ईंधन की कमी से उद्योग धंधों के साथ ही जनजीवन का चक्का जाम हो जाने का अंदेशा तो पैदा हुआ ही है, साथ ही साथ खाद्य संकट के बादल भी मंडराने लगे हैं। लेकिन इन सबके बीच भारत तेजी से उम्मीद के केंद्र के रूप में उभरा है। दुनिया का हर देश भारत की ओर ललचाई नजर से देख रहा है। हर कोई चाहता है कि इस संकट काल में भारत उसके साथ रहे। स्वास्थ्य आपदा के दौरान जिस तरह तमाम देशों को वैक्सीन और दवाई पहुंचाई गई उससे भारत की अहमियत विश्व भर में बढ़ी है। भारत की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता बढ़ने का ही नतीजा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी भारत अपने निर्यात के लक्ष्य को सहायता से हासिल कर सका है और इस हासिल का प्रभाव यह है कि जीडीपी की दृष्टि से वर्ष 2021–22 में अग्रिम अनुमानों के मुताबिक स्थिर मूल्यों के आधार पर हिस्सेदारी 20.9 प्रतिशत के करीब रहनी है। वर्ष 2020–21 मई में यह आंकड़ा 18.8 प्रतिशत का था। ❑❑

ईश्वर दास महाजन जी
एक प्रेरक व्यक्तित्व

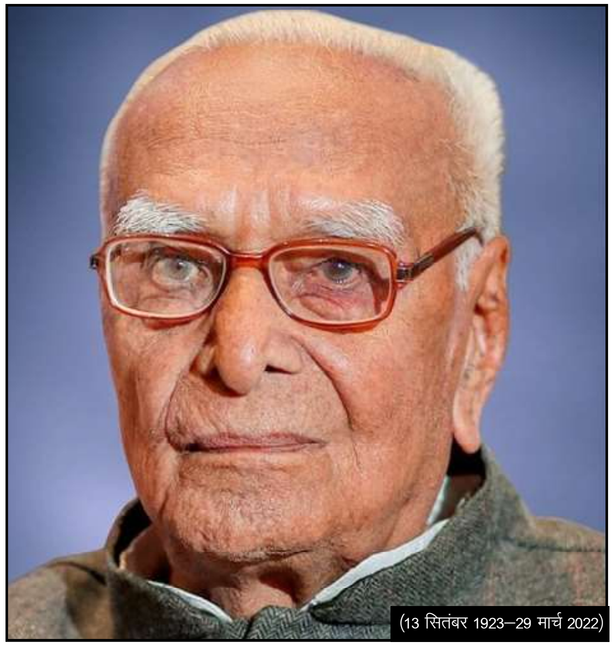
(13 सितंबर 1923–29 मार्च 2022)

स्वदेशी जागरण मंच के प्रथम अखिल भारतीय कोष प्रमुख एवं दिल्ली प्रांत के संयोजक श्री ईश्वर दास महाजन का दिनांक 29 मार्च 2022 को 99 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। संघ के समर्पित कार्यकर्ता और लाखों स्वयंसेवकों के प्रेरणा स्रोत एवं कुशल प्रशासक श्री ईश्वर दास महाजन जी का संपूर्ण जीवन संघ कार्यों को समर्पित रहा। वे लंबे समय तक स्वदेशी जागरण फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे और जीवन के अंतिम क्षण तक वे स्वदेशी पत्रिका के प्रकाशक रहे।

श्री ईश्वरदास महाजन जी का जन्म 13 सितंबर 1923 में शकरगढ़ जिला गुरदासपुर (पंजाब) में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री मिलखी राम जी तथा माताजी का नाम श्रीमती अचरा रानी था। छोटी आयु में ही उनके माता और पिता जी स्वर्ग सिधार गए थे। उनके बड़े भाई श्री राम सरण दास महाजन और तीन बहनों का लालन–पालन उनके चाचा जी श्री मनीराम महाजन जी ने किया। उन्होंने इस परिवार का पालन इतनी लगन से किया कि उन्होंने अपना विवाह भी नहीं किया। अपना सारा जीवन इन्हें पढ़ाने और इन सबको आदर्श जीवन की कला से ओतप्रोत करने में लगा दिया।

ईश्वर जी जब कक्षा सात में पढ़ते थे तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए। दिन प्रतिदिन उनकी रूचि इसमें बढ़ने लगी और अपना ज्यादा समय वहां पर लगाने लगे। वे अत्यंत मेधावी और संस्कारी थे। विद्यार्थी जीवन से ही उनका व्यवहार सभी को प्रभावित करता था। बी.ए. करने के बाद वह 1942 में संघ के प्रचारक बनकर सियालकोट गए थे। वहां पर संघ के कार्य का विस्तार तेज गति से किया। उनके कार्यकाल में संघ की शाखाएं तेजी से बढ़ी और कई कार्यकर्ताओं को संघ के प्राथमिक शिक्षा वर्ग में भेजा। भारत विभाजन के बाद उन्हें शिमला जिला प्रचारक के नाते भेजा गया। वहां पर भी सफलतापूर्वक संघ कार्य का प्रसार किया। अपनी योग्यता और कुशलता के कारण बहुत सम्मानित लोगों से संपर्क साधकर उन्हें संघ से जोड़ा। कुछ वर्षों बाद उन्हें करनाल जिला का काम सौंपा गया। इनके कार्यकाल में करनाल से बहुत प्रचारक संघ कार्य के विस्तार के लिए निकले।

1952 में संघ कार्य प्रचारक के कार्य से मुक्त होकर उन्होंने बी.टी. की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने 1953 में अंबाला जिला कार्यवाह के नाते 10 वर्षों तक कार्य किया। अंबाला नगर में एस.ए. जैन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया और 1953 में ही दिल्ली में निर्मल जी से उनका शुभ विवाह संपन्न हुआ। अंबाला में ही उन्होंने इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। दोनों ही अध्यापन का कार्य करते थे। ईश्वर जी संघ कार्यों में पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते और श्रीमति निर्मल महाजन जी सेवा एवं अन्य सामाजिक कार्यों में समय लगाती थी।

1963 में संगठन की योजना से ईश्वर जी दिल्ली आए। यहां पर डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीजीटी इतिहास के नाते कुछ वर्षों तक अध्यापन किया और फिर प्रधानाचार्य बने। वे 1967 में योजनानुसार भारतीय जनसंघ दिल्ली प्रदेश के मंत्री बनाये गये। 1973 में दिल्ली नगर निगम के सदस्य बने और स्थाई समिति के अध्यक्ष चुने गए। दिनांक 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल के दौरान वे 19 माह जेल में रहे।

1977 में उन्हें दिल्ली महानगर परिषद का डिप्टी लीडर चुना गया। कुछ वर्षों बाद ईश्वर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में संलग्न हो गए। उन्होंने भाग कार्यवाह, विभाग संचालक और प्रांत कार्यवाह के नाते बहुत कार्य किए। इनकी योग्यता और कुशलता के कारण संघ का कार्य तीव्र गति से बढ़ा। ईश्वर जी ने कई साथियों को लेकर 1 मई 1978 को विवेकानंद स्कूल आनंद विहार में शुरू किया।

दिनांक 31 मार्च 2022 को संपन्न उनकी श्रद्धांजलि सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, श्री विजय गोयल, कई वर्तमान और पूर्व सांसद, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल, स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन व बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

स्वदेशी जागरण मंच के समस्त कार्यकर्ता उनके देहावसान पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और भगवान से उनकी सदगति की कामना करते हैं। ❑❑

ऊर्जा का मूल्य बढ़ाइए, खपत घटाइए

यूक्रेन के युद्ध ने ईंधन तेल की समस्या को सामने लाकर खड़ा कर दिया है. कुछ माह पूर्व विश्व बाजार में कच्चे तेल का दाम 80 रुपए प्रति बैरल था जो बढ़कर वर्तमान में 110 रुपए हो गया है। आगे इसके 150 डॉलर तक चढने की संभावना बन रही है. ऐसी परिस्थिति में वर्तमान में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 130 रुपए प्रति लीटर तक होने की संभावना है। हमारे लिए यह संकट है क्योंकि हम अपनी खपत का लगभग 80 प्रतिशत तेल आयात करते हैं। यूक्रेन युद्ध अथवा ऐसे ही अन्य संकट के कारण यदि तेल की सप्लाई कम हो गई और इसके दाम बढ़ गए तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। हमारे पास ऊर्जा के दूसरे स्रोत भी नहीं है। तेल यूं ही कम है। कोयला हमारे पास लगभग आने वाले 150 वर्ष की सामान्य जरूरत के लिए हैं परंतु जैसे–जैसे हम कोयले का खनन करते हैं वैसे–वैसे उसकी गुणवत्ता कम होती जाती है और इसलिए हम वर्तमान में ही कोयले का भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं। यूरेनियम भी अपने देश में कम है जिसके कारण हम परमाणु ऊर्जा नहीं बना सकते हैं।

हमारे पास केवल दो स्रोत बचते हैं – सोलर एवं हाइड्रोपावर। सोलर के विस्तार के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं और इसमें तेजी से वृद्धि भी हुई है परंतु आकलनों के अनुसार इस तीव्र वृद्धि के बावजूद 2050 में सोलर ऊर्जा से हम केवल अपनी 14 प्रतिशत जरूरतों की पूर्ति कर सकेंगे। इसलिए सोलर पावर हमारे उर्जा सुरक्षा का स्तंभ नहीं बन सकता है। हाइड्रोपावर की भी सीमा है क्योंकि तमाम नदियों के ऊपर बंपर से बंपर जुड़े हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले ही लग चुके हैं। बची हुई नदियों के ऊपर हम हाइड्रोपावर लगा भी दें तो भी इनके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भारी है। जैसे पाया गया है कि हाइड्रोपावर के बड़े तालाबों में मच्छर पैदा होते हैं और उन क्षेत्रों में मलेरिया का प्रकोप अधिक होता है। पानी की गुणवत्ता का ह्रास होता है। नदी का सौंदर्य जाता रहता है। मछलियां मरती हैं और

सेवा क्षेत्र में सॉफ्टवेयर, संगीत, ट्रांसलेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आते हैं जहां पर कम ऊर्जा में अधिक उत्पादन किया जाता है। यदि हम अपनी आय को सेवा क्षेत्र से हासिल करें तो हम कम ऊर्जा में अधिक आय हासिल कर सकते हैं।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

जैव विविधता समाप्त होती है। अतः जब हम हाइड्रोपावर बनाते हैं तो हमारे जीवन स्तर पर एक साथ दो विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। एक तरफ हमें बिजली उपलब्ध होती है जिससे जीवन स्तर पर सुधार होता है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य, पानी और सौंदर्य का ह्यास होता है जिससे हमारे जीवन स्तर में गिरावट आती है. अंततः हाइड्रोपावर से कोई विशेष लाभ होता है ऐसा नहीं दिखता। फर्क सिर्फ इतना है कि हाइड्रोपावर से बनी हुई ऊर्जा का उपयोग अमीर ज्यादा करते हैं जबकि पर्यावरणीय दुष्प्रभाव आम आदमी पर अधिक पड़ता है. इसलिए देश के लिए हानिप्रद होते हुए भी हाइड्रोपावर को बढ़ाया जा रहा है परंतु इससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा स्थापित नहीं होती क्योंकि इसकी सीमा है।

जब हम खेती की जमीन पर बायोडीजल बनाने के लिए गन्ने का उत्पादन बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में गेहूं, चावल और अन्य फल, सब्जी का उत्पादन घटता है जिससे हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।

एक और घरेलू स्रोत बायोडीजल अथवा एथेनॉल का है। यहां संकट खाद्य सुरक्षा का है। जब हम खेती की जमीन पर बायोडीजल बनाने के लिए गन्ने का उत्पादन बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में गेहूं, चावल और अन्य फल, सब्जी का उत्पादन घटता है जिससे हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। पानी का भी संकट बनता है क्योंकि गन्ने के उत्पादन में गेहूं की तुलना में लगभग 10 गुना पानी अधिक प्रयोग होता है। लगभग संपूर्ण देश में भूमिगत जल का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है जिसके कारण हम बायोडीजल का उत्पादन भी नहीं बढ़ा सकेंगे। परमाणु ऊर्जा की भी समस्या है क्योंकि यूरेनियम अपने देश में है ही नहीं। इसका एक विकल्प थोरियम है। लेकिन थोरियम से यूरेनियम बनाने में हम फिलहाल बहुत पीछे हैं। चीन इसी वर्ष थोरियम से चलने वाले एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर को शुरू करने जा रहा है जबकि हम केवल अभी ड्राइंग बोर्ड पर ही सीमित है। इसलिए अगले 20–30 वर्षों में हम थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा बनाएंगे इसकी संभावना नहीं के बराबर है।

इस परिस्थिति में हम ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाकर किसी भी तरह से अपनी ऊर्जा सुरक्षा स्थापित नहीं कर सकते हैं। हमारे पास केवल एक उपाय है कि हम अपनी खपत को कम करें। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में बताया गया कि विश्व के ऊपरी 10 प्रतिशत लोगों द्वारा 50 प्रतिशत ऊर्जा की खपत होती है। अतः यदि हम ऊर्जा के दाम में भारी वृद्धि करें तो इसका अधिक प्रभाव ऊपरी वर्ग पर पड़ेगा; और यदि इस पर लगाए गए टैक्स का उपयोग हम आम आदमी के हक में करें तो आम आदमी के जीवन स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना अधिक खर्च उसके द्वारा महंगी ऊर्जा की खरीद में किया जाएगा उससे ज्यादा लाभ उसे सार्वजनिक सुविधाओं जैसे बस की उपलब्धता से हो सकता है।

इसलिए सरकार को तेल और बिजली दोनों पर भारी "उर्जा सुरक्षा" टैक्स आरोपित करना चाहिए। इनके दाम में भारी वृद्धि करनी चाहिए। तेल पर 100 रुपए प्रति लीटर और बिजली पर 20 रुपए प्रति यूनिट का ऊर्जा सुरक्षा टैक्स लागू कर देना चाहिए। साथ–साथ जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने जनता को 300 यूनिट तक की बिजली की खपत मुफ्त करा दी है उसे सम्पूर्ण देश में लागू करना चाहिए जिससे आम आदमी पर तेल और बिजली के बढ़े हुए दाम का प्रभाव न पड़े।

ऊर्जा सुरक्षा स्थापित करने का दूसरा उपाय है कि हम मैन्युफैक्चरिंग के आधार "मेक इन इंडिया" को बढ़ाने के स्थान पर सेवा क्षेत्र के आधार पर "सर्वड फ्रॉम इंडिया" के विस्तार पर ध्यान दें। बताते चलें कि 100 रुपए की आय बनाने में जितनी उर्जा मैन्युफैक्चरिंग में लगती है उसका केवल दसवां हिस्सा सेवा क्षेत्र में लगता है। सेवा क्षेत्र में सॉफ्टवेयर, संगीत, ट्रांसलेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आते हैं जहां पर कम ऊर्जा में अधिक उत्पादन किया जाता है। यदि हम अपनी आय को सेवा क्षेत्र से हासिल करें तो हम कम ऊर्जा में अधिक आय हासिल कर सकते हैं। अतः सरकार को उत्पादित माल जैसे कार, एलमुनियम, स्टील आदि के निर्यात पर भी भारी निर्यात टैक्स लगाना चाहिए जिससे इनका उत्पादन कम हो और देश में ऊर्जा की खपत कम हो। साथ–साथ सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे कि हम कम ऊर्जा में भी पर्याप्त आय को हासिल कर सके। ऊर्जा का संकट आगे गहराने की स्थिति में है। इस दिशा में सरकार को शीघ्र कदम उठाने चाहिए। ❑❑

दिल्ली का बजटः
झूठ की चासनी में जुमलों की सौगात

अरविंद केजरीवाल ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा देश के नेता बनने की है, लेकिन उसके लिए जो रास्ता उन्होंने चुना है वह कर के नेता बनने वाला नहीं कह कह के नेता बनने वाला है। वह संभवतः देश की जनता को इतने कम समझ वाली मानते हैं कि जो चाहे दावा और वायदा कर डालते हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि जो कह रहे हैं वह खालिस बकवास के अलावा कुछ भी नहीं है।

पिछले सात साल से वह दिल्ली के मुख्यमंत्री है और उनके हर भाषण में उनका एक ही जुमला होता है, दिल्ली का स्कूल ठीक कर दिया दिल्ली का अस्पताल ठीक कर दिया। अब वही बता सकते हैं कि अगले कितने साल तक वह इस जुमले को दोहराते रहेंगे। अभी दिल्ली का बजट आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रस्तुत किया। 75,800 करोड़ के दिल्ली के बजट में क्या ऐसा किया है कि जो हर साल लाखों रोजगार के अवसर उत्पन्न हो जाएंगे, केजरी सरकार ने कोई स्पष्टता नहीं दी है। सिवाय इसके कि बपरोला दिल्ली में एक नया इलेक्ट्रानिक सिटी बनाने की घोषणा के। बाकी जितने भी रोजगार सृजन के विकल्प बताए गए हैं, सब पहले से चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने उसपर नया लिफाफा चढ़ाने का प्रयास किया है।

दिल्ली वर्षों से खुदरा और थोक कारोबार का गढ़ रही है। यहां से पूरे भारत के लोग सामान खरीद कर ले जाते रहे हैं, इसके लिए दिल्ली सरकार 100 करोड़ रुपये खर्च कर रिटेल व्यवसाय को आकर्षक बनाने का जो दावा कर रही है, दरअसल वह निजी व्यवसायियों के कारोबार को अपने जरिए होने का दावा करने का एक सस्ता फार्मूला है। ठीक उसी तरह जैसे पहले रोजगार का पोर्टल बनाकर रोजगार मुहैया कराने का दावा केजरीवाल ने किया था। नौकरी देने वाले और नौकरी मांगने वाले का नाम अपने पोर्टल पर ले आओ और रोजगार देने का दावा कर डालो।

लिफाफा बदलने के इस काम का नमूना इस उदाहरण से देखा जा सकता है। दिल्ली में पांच बड़े रिटेल मार्केट हैं। 2022 के बजट में कहा गया है कि 100 करोड़ के लागत से

केजरीवाल के वे सभी वायदे नारे दिल्ली तक अभी भी नहीं पहुंचे जो वे दूसरे राज्यों में चुनाव जीतने के लिए करते आ रहे हैं।

– विक्रम उपाध्याय

सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग मार्केट में आए और रोजगार बढ़े। जरा चांदनी चौक बाजार में ही जाकर देखें। वहां आज तक महिलाओं के लिए उचित शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। ढ़ांचागत विकास की मांग काफी समय से व्यापारी कर रहे हैं। पिछले अक्टूबर में दिल्ली के वित मंत्री मनीष सिसोदिया ने वहां का दौरा भी किया, लेकिन जिस बजट को रोजगार बढ़ाने वाला बजट केजरीवाल की सरकार बता रही है वह तो चांदनी चौक के बाजार को भी ठीक करने के लिए पैसे आवंटित नहीं कर रही है। गांधी मार्केट, कृष्णा मार्केट, सरोजिनी नगर करोल बाग में पिछले छह साल में कितना विकास हुआ है यह बताने की स्थिति में खुद केजरीवाल भी नहीं है।

केजरीवाल को इतना जरूर मालूम है कि देश में आने वाले सभी चुनावों में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। पहले कोरोना, फिर रूस –यूक्रेन युद्ध, अमेरिका का रूस ईरान और चीन पर प्रतिबंध और फिर पूरे विश्व में छायी महंगाई। लोगों के सामने समस्याएं तो होंगी, जिसका तत्काल हल ढूंढने में सभी सरकारें लगी हैं। लेकिन केजरीवाल को इसमें लगना नहीं है। बेरोजगारी की समस्या में अपनी झूठ की राजनीति का छौंक लगाना है। इसके लिए उन्हें कुछ खास नहीं करना बस झूठ ही तो बोलना है तो उसकी आदत पहले से ही बनी हुई है।

अगले पांच साल में दिल्ली में 20 लाख रोजगार देने के वायदे वाले बजट में प्रावधान भले ही ना किया हो दावे तो किए ही जा सकते हैं। जैसे अभी तक किए गए हैं। मसलन केजरीवाल ने पोर्टल में लोगों का नाम चढ़ायाा और पिछले पांच साल में जितनी भी निजी कंपनियों में नौकरी मिली सब पर अपने श्रेय का लिफाफा चढ़ा दिया। 10 लाख नौकरियां निजी क्षेत्रों ने दिया, जिसे केजरीवाल ने अपने नाम कर लिया। खुद ही विधानसभा में डरते डरते यह दावा किया कि उन्होंने भी पिछले छह साल में 53 हजार नौकरियां दी हैं। वो दावा भी कितना सच्चा है यह तो केजरीवाल ही जानते हैं। यदि इस दावे में सच्चाई होती तो सूचना के अधिकार के माध्यम से यह जानकारी क्यों आती कि पिछले छह साल में केवल 464 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली है। विकास के नाम पर इतना बड़ा भोपूं।

पंजाब में उन्होंने हर महिला को एक हजार रूपया प्रति महीना देने का वायदा तो किया है, लेकिन सात साल से दिल्ली में सरकार चलाने के बावजूद किसी महिला को एक भी पैसा नहीं दिया है।

केजरीवाल जानते हैं कि गुजरात, हिमाचल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलांगना के चुनाव होने वाले हैं। अधिकतर राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होना है। बीजेपी से पार पाना भले ही मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस को हटा कर उसकी जगह अपनी पहुंच बनाने का यह मौका है। केजरीवाल को यह भी मालूम है कि मुश्किल से दो करोड़ की जनता वाली दिल्ली में उनका प्रदर्शन ब़ड़े राज्यों में कोई मायने नहीं रखता। ना ही दिल्ली में उनकी कथित उपलब्धि की छाप ही कहीं दिखाई पड़ सकती है।

आधी दिल्ली केंद्र के अधीन है, वहां केंद्र सरकार के अपने सुविधा केंद्र हैं। अपने अस्पताल हैं, अपने स्कूल हैं। फिर निजी क्षेत्र भी यहां काफी मजबूत है। अकेले दिल्ली में 100 से अधिक बड़े निजी अस्पताल हैं। 50 प्रतिशत स्कूलों की संख्या निजी क्षेत्र की है। केजरीवाल ने अभी तक दिल्ली की उन सारी समस्याओं को केंद्र के मत्थे मढ़ दिया है, जब जब वह पूरी तरह विफल रहे हैं। दिल्ली में जब प्रदूषण का लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वह केंद्र के बिजली घरों और हरियाणा व पंजाब के किसानों पर दोष मढ़कर निकल जाते हैं। दिल्ली में पानी का जब संकट आता है तो वह भी हरियाणा का दिया हुआ बता कर छुप जाते हैं। जब कभी किसी ने यमुना को साफ करने के उनके वायदे के बारे में पूछा तो वह एक नई तारीख बता देते हैं।

केजरीवाल के वे सभी वायदे नारे दिल्ली तक अभी भी नहीं पहुंचे जो वे दूसरे राज्यों में चुनाव जीतने के लिए करते आ रहे हैं। पंजाब में उन्होंने हर महिला को एक हजार रूपया प्रति महीना देने का वायदा तो किया है, लेकिन सात साल से दिल्ली में सरकार चलाने के बावजूद किसी महिला को एक भी पैसा नहीं दिया है। उत्तराखंड में चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल ने यह तो घोषणा कर दी थी कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, लेकिन दिल्ली में नौकरी देने के बजाय नौकरी का पोर्टल लांच करने की बात करते हैं। गोवा और पंजाब को नशामुक्त करने का वायदा तो उन्होंने किया, लेकिन दिल्ली की हर गली में शराब की दुकान लाइसेंस दे दिया है। उन्हें नहीं मालूम कि जनता विकास और विकास के भोपूं में अंतर खूब समझती है। दिल्ली और पंजाब को छो़ड़ केजरीवाल ने जिस राज्य के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मरीद्वार खड़े किए, उनमें 10 में से नौ की जमानत जब्त हुई है। पर क्या करें बंदा झूठ बोलने की आदत से मजबूर है। ❑❑

खुशी की गिनती में पीछे, पर खुशहाली में अव्वल है भारत

आनंद की कल्पना भारतीयों के लिए नई नहीं है। हर भारतीय की मन से यह इच्छा रहती है कि वह जीवन में आनंद प्राप्त करें। यह बात सही है कि भारतीयों के आनंद की परिभाषा पाश्चात्य जगत के परिभाषा से अलग है। पाश्चात्य जगत गिने जाने वाले आनंद में विश्वास करता है जबकि भारतीय अंतरमन में शाश्वत आनंद के अनुभव में विश्वास करता है जो गिनने–गिनाने से परे होता है। गिने जाने वाले आनंद को हम खुशी कह सकते है क्योंकि यह बदलते बाह्य जगत के प्रभाव का परिणाम है न कि आंतरिक अनुभूति का प्रत्यय। ऐसी खुशी की एक रिपोर्ट हर साल आती है जो हर साल दुनिया के खुश लोगों के बारे में जानकारी हासिल करती है और जहाँ इस तरह के खुश लोग ज्यादा है उस देश को 'खुशहाल' देश जाहिर करती है। भारत ऐसी गिनती वाली खुशी के देशों में हमेशा पीछे रहता है। इसका मतलब यह नहीं लेना चाहिए कि भारत के लोग खुशी को नहीं समझते और वे खुश नहीं रहते। खुशी की गिनती में हम जरूर पीछे होंगे लेकिन आनंद की अनुभूति में शायद दुनिया में सबसे आगे है।

खुशी की रिपोर्ट

दुनिया के कुछ विशेषज्ञों ने मिलकर बनाई गई दुनिया की 'खुशहाली रिपोर्ट 2022' हाल ही में प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020–21 वर्ष में खुश देशों के सूची में भारत की स्थिति 146 देशों में 136 नंबर पर थी। इसका मतलब यह है कि भारत सबसे कम खुश देशों में आता है। अर्थात सबसे खुश देशों में जैसे यूरोपीय समृद्ध देश है वैसे अमरीका, कनडा और अरब जैसे और भी समृद्ध देश ही है। इससे यह बात तो स्पष्ट है कि इस खुशी का नाता सुख–समृद्धि से ज्यादा है। कुछ संकेतों को सामने रखकर देश की परिस्थिति और उससे संबंधित देश के लोगों की प्रतिक्रिया को आधार बनाकर खुशी की यह रिपोर्ट तैयार की जाती है।

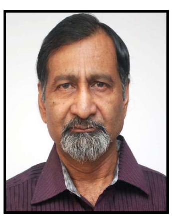

भारतीयों के आनंद की परिभाषा पाश्चात्य जगत के परिभाषा से अलग है। पाश्चात्य जगत गिने जाने वाले आनंद में विश्वास करता है जबकि भारतीय अंतरमन में शाश्वत आनंद के अनुभव में विश्वास करता है जो गिनने–गिनाने से परे होता है।

– अनिल जवलेकर

खुशी जानने का तरीका

रिपोर्ट बनाने वाले यह विशेषज्ञ 'ग्यालप सर्वे' से जमा डाटा का उपयोग करते है। ग्यालप एक जनमत संग्रह करने वाली कंपनी है जो सवाल–जवाब के जरिये ऐसे सर्वे करती रहती है। खुशी तय करते समय कुछ संकेतों का संदर्भ लिया जाता है जिसमें देश में प्रति

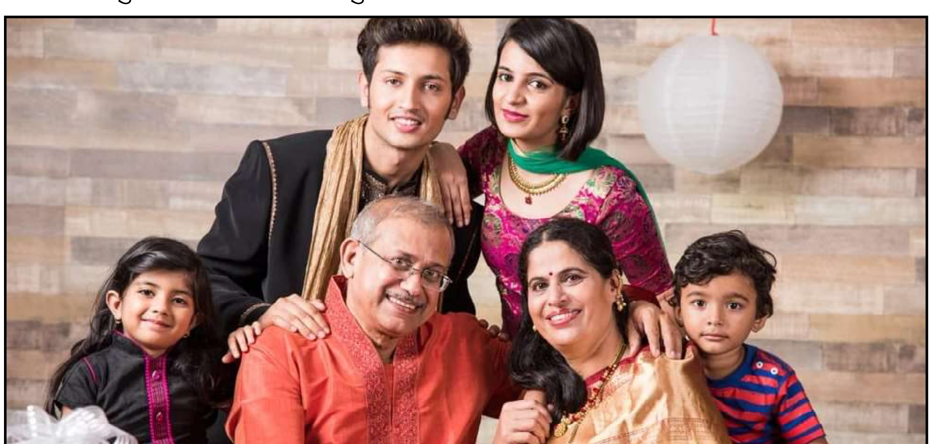

व्यक्ति 'जीडीपी' कितनी है, सामाजिक सुरक्षा का क्या हाल है, स्वस्थ आयु की संभावना क्या है, जीवन जीने की कितनी स्वतंत्रता है, लोग कितने उदार है, भ्रष्टाचार और आतंक की स्थिति कैसी है तथा लोगों में आत्मविश्वास कैसा है वगैरे मुख्य है। यहाँ यह भी बात ध्यान रखना जरूरी है कि विश्लेषण का आधार 'सर्वे' के सवाल–जवाब पर निर्भर होता है जो सवाल व्यक्ति को पूछे गए है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि व्यक्ति अपने समझ के अनुसार सवाल के जवाब देता है।

खुशी की अभिव्यक्ति उपयोगी

रिपोर्ट उसी खुशी की बात करती है जो बाह्य वस्तु व सेवा के सेवन एवं अच्छी सामाजिक सुरक्षा, अच्छा सामाजिक वातावरण और अच्छी आर्थिक स्थिति से प्राप्त होती है और यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह व्यक्ति सापेक्ष तथा परिस्थिति सापेक्ष होती है। इसलिए यह खुशी व्यक्ति की मात्र अपनी भावना की अभिव्यक्ति है जो उसने विशिष्ट संदर्भ में विशेष सवाल के जवाब देते समय महसूस की है। इससे खुशी का एक सामान्य अनुमान लगाया जा सकता है न कि खुशी की कोई निश्चिति की जा सकती है। हाँ, खुशी की यह सोच और अभिव्यक्ति सरकार को अपनी आर्थिक नीति विशेष तौर पर जनसाधारण को सुख सुविधा मिले ऐसी व्यवस्था बनाने में मदद कर सकती है और यही इस रिपोर्ट से अपेक्षित है।

आनंद और खुशी अलग–अलग

खुशी एक मानसिक स्थिति कही जा सकती है जो हर व्यक्ति के मनःस्थिति अनुसार बदलती है। और यह बात कई संदर्भ में अलग–अलग होती है। कम या ज्यादा खुशी की बात भी चर्चा का विषय होती है। ईर्षा और स्पर्धा के जमाने में दूसरे की हार भी खुशी का कारण बन सकती है। इसलिए खुशी की बात खुशी के व्यक्त संदर्भ में ही देखी जानी चाहिए या समझनी चाहिए और उसकी तुलना आनंद से नहीं करनी चाहिए। आनंद किसी भी खुशी से अलग माना जाता है क्योंकि उसकी भारतीय परिभाषा आध्यात्मिक ज्यादा है और भौतिक जीवन संघर्ष में मिलने वाली खुशी से अलग है। यह माना जाता है की खुशी का संदर्भ सुख–समृद्धि से है और संसाधनों के होने न होने से जैसे यह बढ़ती या घटती है वैसे ही सामाजिक सुरक्षितता वगैरे का भी उस पर असर होता है। 'डर' के माहौल में समृद्धि भी खुशी नहीं दे सकती। इसलिए जीवन की सुरक्षितता और जीवन जीने योग्य सामाजिक सहकारिता महत्वपूर्ण कही जा सकती है। निश्चित तौर पर सांसारिक जीवन में सुख के साधन होना आवश्यक है और उसका अभाव व्यक्ति और समाज के अस्वस्थता का कारण बन सकता है तथा खुशी कम होने का कारण भी माना जा सकता है। इसलिए सरकार भी भौतिक समृद्धि को आवश्यक मानती है और समाज के सभी घटकों का जीवन सुखमय हो ऐसी व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास करती है जिससे लोगों की खुशी बढ़े और देश भी खुशहाल हो।

व्यक्ति और समाज जब समृद्ध होकर भौतिक जीवन में सुखी होता है तभी अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर पाता है और तब वह समाज खुशहाल देश की पहचान बनता है।

भारत का हाल बहुत अच्छा नहीं है

निश्चित तौर पर भारत अभी भी विकासशील देश है। भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी समृद्ध देशों के मुक़ाबले बहुत ही कम है और उससे ही समृद्धि और खुशी की बात आँकी जा सकती है। भारत सरकार को अपनी 80 प्रतिशत जनता को मुफ्त में अनाज देना पड़ता है और रोजगार की उपलब्धि के लिए रोजगार गारंटी योजना चलानी पड़ती है इससे इसका अंदाजा हो सकता है। गरीबी लोगों को बहुत सी वस्तु एवं सेवा के सेवन से वंचित रखती है जो खुशहाली में बाधा बनती है। आयु–संभाव्यता की बात करें तो जापानी भारतीयों से 10 साल ज्यादा जीने की उम्मीद रख सकता है। भारतीयों की आयु–संभाव्यता कम होने की वजह आरोग्य सुविधा की कमी कही जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा का हाल अपने देश में बहुत अच्छा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ है। निश्चित ही भारत को अपनी कायदा और कानून व्यवस्था और उससे जुड़ी न्याय व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा तभी लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। यह जरूर है कि पिछले कुछ सालों से आतंकवाद कम हुआ है जो अच्छी बात है।

यह खुशी भी महत्वपूर्ण है

दुनिया जिसे खुशी समझती है वह भौतिक संसाधनों के संदर्भ में लागू होती है और ऐसी खुशी का अपना महत्व है जिसे नकारा नहीं जाना चाहिए। यह सही है कि भारतीयों ने अपना आनंद भौतिकता के त्याग में देखा है। लेकिन यह भी सही है कि भारतीय दर्शन शास्त्र जीवन के आनंद में भी विश्वास करता है और गृहस्थाश्रम में कर्म द्वारा प्राप्त भौतिक समृद्धि और सुख महत्वपूर्ण मानता है। निश्चित ही इस सुख से मिलने वाली खुशी महत्व की है। व्यक्ति और समाज जब समृद्ध होकर भौतिक जीवन में सुखी होता है तभी अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर पाता है और तब वह समाज खुशहाल देश की पहचान बनता है। ❑❑

शिक्षा के भारतीयकरण की अनिवार्यता

चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद दिलाई जाने वाली शपथ को लेकर चली आ रही बरसों पुरानी परंपरा में बड़ा बदलाव हो रहा है। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में भारत के शीर्ष चिकित्सा नियामक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सुझाव दिया है कि डाक्टरों के स्नातक समारोह के दौरान उन्हें हिप्पोक्रेटिक (पाखंडी) शपथ की जगह चरक शपथ दिलाई जाए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दिशा निर्देशों के तहत डॉक्टर अब चरक शपथ लेंगे। चरक शपथ लेते समय वह वचन देंगे कि ''न अपने लिए न ही दुनिया में मौजूद किसी वस्तु या आर्थिक फायदा पाने के लिए, बल्कि सिर्फ इंसानियत की पीड़ा को खत्म करने के लिए मैं अपने मरीजों का इलाज करूंगा।'' चिकित्सा आयोग ने अपने दिशानिर्देश में 10 दिन के लिए योग पाठ्यक्रम शामिल किए जाने की भी अनुशंसा की है। आयोग की इस पहल को चिकित्सा शिक्षा विभाग के भारतीयकरण के नजरिए से देखा जा रहा है।

जरूरत है कि हम अपने विशाल ज्ञान भंडार के जरिए पिछले मैकाले पद्धति को चुनौती दें। हमें भक्ति के साथ–साथ सूफी आंदोलनों के अध्ययन को भी प्रोत्साहित करना होगा। शिक्षा के भारतीकरण की संकीर्ण रूप से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए इसे एक विशिष्ट विचारधारा रंग या विचार प्रक्रिया के साथ नहीं पहचाना जाना चाहिए, बल्कि यह सही मायने में राष्ट्रवादी होना चाहिए।

– डॉ. जया कक्कड़

मालूम हो कि अब तक डॉक्टर जो शपथ लेते थे उसकी उत्पत्ति कभी ग्रीस से हुई थी जो समय के साथ दुनिया भर में फैली। हिप्पोक्रेटिक शपथ में डॉक्टर शपथ लेते हैं कि ''वह अपनी गरिमा और चेतना के अनुरूप मरीज के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे तथा उनकी निजता का सम्मान करेंगे।'' जबकि चरक शपथ में अब वचन देना होगा कि ''वह अपनी पूरी योग्यता के साथ सही निर्णय लेते हुए मरीज का उपचार करेंगे। मरीज का परीक्षण करते समय भी वह इलाज पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आर्थिकी का ध्यान दिए बगैर मरीजों और उनके परिवारों की निजता कायम रखेंगे।'' यह नई शपथ महर्षि चरक की लिखी पुस्तक चरक संहिता से ली गई है। महर्षि चरक दुनिया की सबसे प्राचीन कही जाने वाली आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के शीर्ष विशेषज्ञ माने जाते हैं।

इन दिनों बदलते परिवेश के नए इतिहासकार इतिहास को पहले से स्थापित तरीकों से अलग पेश करना चाहते हैं। आज के इतिहास लेखकों में देवत्व का पुट डालने में भी कोई गुरेज नहीं होती। इस बारे में अगर कोई सवाल खड़े करें तो ऐसे लोगों का मानना है कि

यह अब तक की हुई चूक को ठीक करने का प्रयास है। प्रसिद्ध मार्क्सवादी इतिहासकार डीडी कोसांबी भी मानते हैं कि भारतीय इतिहास वह नहीं था जो हमें बताया गया। उन्होंने लिखा है कि यूरोपीय मत मूल रूप से गलत है, क्योंकि यूरोपियन लोगों द्वारा लिखा गया इतिहास भारत का समग्र प्रस्तुत नहीं करता है। यूरोपीय इतिहासकारों में दरअसल भारतीय अतीत का अध्ययन करने की समझ कम थी। उन्होंने अपने इतिहास लेखन में कुछ राजवंशों व उनसे जुड़े युद्धों और उन युद्धों की कहानियों पर आख्यानों के साथ चर्चा की है। ऐसे में इतिहास लेखन का काम विदेशी विद्वानों और उनके भारतीय अनुचरों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। जब हम इतिहास का भारतीयकरण करने का प्रयास कर रहे हैं तो यह उन्हीं की तरह उपाख्यान और पौराणिक कथाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए। इतिहास सिर्फ तर्कपूर्ण ही नहीं, बल्कि साक्ष्य आधारित और प्रमाणित होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस इतिहास को झुठलाना, इसका खंडन करना कठिन हो।

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने शिक्षा की मैकाले प्रणाली में बड़े बदलाव के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने कहा कि मैंकाले की पद्धति प्रभावी तो है लेकिन हानिकारक बहुत है। इस पद्धति से भारतीयों में हीन भावना पैदा होती है। इसने भारत की पारंपरिक शिक्षा को अंग्रेजी के अपरिचित पाठ्यक्रम में बदल दिया है। यह हमें औपनिवेशिक मानसिकता की ओर ले जाता है। इसने हमें अपनी विरासत से दूर कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्रभाव में हम जानबूझकर उपयोगी और उत्पादक विचारों और दर्शन से दूर हो गए हैं जो कि हमारी प्राचीन सभ्यता का मूल है।

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने शिक्षा की मैकाले प्रणाली में बड़े बदलाव के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने कहा कि मैंकाले की पद्धति प्रभावी तो है लेकिन हानिकारक बहुत है। इस पद्धति से भारतीयों में हीन भावना पैदा होती है।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक अभिनव राष्ट्रवादी पाठ्यक्रम तैयार किया था। आजादी से पहले भी भारतीय दिमागों को गुलामी की ओर ले जाने वाली पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। सन 1888 में अबू मौलवी द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि साहित्य और विज्ञान को स्थानीय और भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा के भारतीयकरण के बारे में शुरू हुई बहस कोई नई नहीं है और न ही इसे आज के दौर के दक्षिणपंथी विद्वानों द्वारा शुरू किया गया है।

शिक्षा की मैकाले प्रणाली ने विदेशी अवधारणाओं को अनजाने में स्वीकार करने और अपनाने का नेतृत्व किया है, लेकिन अब वास्तव में शिक्षा के भारतीयकरण को आगे कर मैकाले की हानिकारक विरासत को खत्म करने और अपनी प्राचीन और पारंपरिक विरासत के साथ फिर से जुड़ने का समय आ गया है। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से देश में भूरे साहब और उनके उत्पादनों की कल्पना की। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के जरिए हमारे पाठशालाओं, गुरुकुलों और मदरसों में दखलअंदाजी करते हुए संस्कृत, फारसी को बेकार बताते हुए इन्हें व्यवस्थित रूप से हटाने की कोशिश की गई। इसका एकमात्र उद्देश्य हमारे प्राचीन ज्ञान को नष्ट करने का एक संगठित प्रयास था। मैकाले पद्धति के जरिए बौद्धयान, पिंगला, आर्यभट्ट, भास्कर आचार्य के इतिहास को मिटाने की कोशिश हुई तथा उनकी जगह यूक्लिड और पाइथागोरस को दे दी गई। मैकाले पद्धति के जरिए हमारे विशाल ज्ञान भंडार को कम किया गया। आमतौर पर भारतीय छात्र छः ऋतु के बारे में परिचित थे, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के दबाव में भारतीय छात्र भी केवल यूरोप के चार मौसमों के बारे में ही जान पाए। मैकाले की पद्धति के जरिए भारत की प्राचीनता और संस्कृति को भी केवल एक औपनिवेशिक व्याख्या के जरिए कमतर कर बच्चों के दिमाग में डाला गया। आजादी के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। देश का नेतृत्व कर रहे लोगों ने सात समंदर पार बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया गया। यहां तक कि चोलों और ललितादित्य जैसे स्वदेशी नायकों को भी लगभग भुला दिया गया। हमारे समृद्ध इतिहास को साजिश के तहत धीरे–धीरे गायब किया गया और हमें इतिहास के नाम पर आक्रमणकारियों की यात्राएं थमा दी गई। शेक्सपियर के नाटकों की धूम मची, लेकिन हमारे कालिदास को विस्मृत कर दिया गया।

जहां तक धर्म की शिक्षा और कट्टरता का सवाल है तो हिंदू धर्म आज भी पश्चिमी और मध्य पूर्वी धार्मिक दृष्टिकोणों की तुलना में अनिवार्य रूप से अधिक उदार है। भारत के दो विशल महाकाव्य महाभारत और रामायण अंग्रेजों के आगमन से पहले तक मदरसों में भी

पढ़ाए जाते थे। भारतीय मुस्लिम और भारतीय ईसाई सभी हिंदुओं के साथ रहते आए थे तथा अपने–अपने धर्म कर्म में विश्वास करते थे। यह बात हाल के प्यू सर्वेक्षण में भी सामने आई है। हमारा समाज भारतीय संतों, दार्शनिकों, लेखकों की शिक्षा की वकालत करता रहा हैं, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। हम ज्ञान के लेनदेन वाले समाज के लोग हैं। हमारे यहां के छात्रों को नैतिक विज्ञान में बाइबल से ली गई कहानियां जरूर पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन भारतीय स्रोतों की कहानियों की कीमत पर नहीं। हमारे यहां के सभी छात्रों को मिर्जा गालिब, व्यास, अमीर खुसरो और बाल्मिकी को जरूर पढ़ना चाहिए। काबा और काशी दोनों को हमें प्रबुद्ध करना है। अब समय आ गया है कि हम अपनी प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृति से अपने तिरस्कार को त्यागे और अपनी स्थानीय ज्ञान की विरासत को फिर से आगे बढ़ाएं। इस बात की वकालत हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ राधाकृष्णन ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि एक विशिष्ट कक्षा दिवस की शुरुआत कुछ मिनटों के मौन ध्यान से होनी चाहिए और इसके बाद कबीर, नानक, जीसस, रामानुज, बुद्ध सहित महान विचारकों की शिक्षाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसलिए हम पुष्टि करते हैं कि श्री नायडू के भगवाकरण की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए ताकि महान विचारकों की एक सर्व समावेशी सूची तैयार हो और आलोचनात्मक सोच क्षमता को विकसित किया जा सके। लेकिन ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार की सोच का उद्देश्य किसी का उपदेश नहीं होना चाहिए। दरअसल भारत की सांस्कृतिक विविधता के बारे में सीखते समय समावेशी होना बहुत महत्वपूर्ण है।

निसंदेह भारत की प्राचीन संस्कृति को पुनः प्राप्त करने, उसका पुनर्निर्माण करने और गौरवशाली भारतीय बनने के लिए इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है। लेकिन सांस्कृतिक गौरव को हासिल करते समय साजिश के तहत चलाए जाने वाले जहरीले एजेंडों से भी बचके रहना होगा। जरूरत है कि हम अपने विशाल ज्ञान भंडार के जरिए पिछले मैकाले पद्धति को चुनौती दें। हमें भक्ति के साथ–साथ सूफी आंदोलनों के अध्ययन को भी प्रोत्साहित करना होगा। शिक्षा के भारतीकरण की संकीर्ण रूप से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए इसे एक विशिष्ट विचारधारा रंग या विचार प्रक्रिया के साथ नहीं पहचाना जाना चाहिए, बल्कि यह सही मायने में राष्ट्रवादी होना चाहिए। जिसमें प्राच्य और पाश्चात्य दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शामिल हो, ज्ञान न तो पूरब का है न ही पश्चिम का। ज्ञान पर सबका अधिकार है यह सार्वभौमिक है। ❑❑

लेखिका एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रबंधन विचारक हैं।

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :

http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षो से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC: BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

भविष्य का ईंधन – हाइड्रोजन

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मुख्य श्रोत्र ऊर्जा है। राष्ट्र की आर्थिक शक्ति भी ऊर्जा से ही संचालित होती है। अक्षय ऊर्जा (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सामुद्रिक ऊर्जा), कोयला, भूमि और समुद्र में कच्चा तेल (पेट्रोल डीज़ल) और गैस (सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी) का अधिकतम सदुपयोग राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाता है। वर्तमान में सभी देश आयातित और स्वयं उत्पादित पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी ही सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। उद्योग, परिवहन, घरेलू उपकरण सभी इन पर ही आधारित हैं। आज जब विश्व में रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य एशिया में विक्षोभ की स्थिति के कारण इनकी उपलब्धता बहुत महंगी हो रही है तथा पर्यावरण पर त्राहि त्राहि हो रही है, तब पर्यावरण और सुलभ उपलब्धता के लिए अक्षय ऊर्जा और अन्य साधनों के लिए प्रयत्न हो रहे हैं। भारत की सरकार ने इन चुनौतियों को बहुत पहले ही भाँप लिया था। हमने कोरोना महाकाल में वेक्सीन, वेंटीलेटर, दवाओं में बहुत जल्दी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी। इसी प्रकार भारत सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के लिए अथक प्रयास किए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग के लिए सरकार ने राष्ट्रीय नीति की भी घोषणा की है।

ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है?

ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सर्वोत्तम स्रोत है। इससे प्रदूषण नहीं होता है। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बनाने के लिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोलाइजर नवीकरणीय (अक्षय) ऊर्जा (सोलर, हवा) का प्रयोग करता है। आवर्त सारणी पर हाइड्रोजन पहला और सबसे हल्का तत्त्व है। चूंकि हाइड्रोजन का वजन हवा से भी कम होता है, अतः यह वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती है। इसलिए यह शुद्ध रूप में बहुत कम ही पाई जाती है। मानक तापमान और दबाव पर हाइड्रोजन एक गैर–विषाक्त, अधातु, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन और अत्यधिक ज्वलनशील द्विपरमाणुक गैस है। ऑक्सीजन के साथ दहन के दौरान हाइड्रोजन ईंधन एक शून्य–उत्सर्जन ईंधन है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग ट्रांसपोर्ट, केमिकल, आयरन सहित कई उपक्रमों में किया जा सकता है। इसका उपयोग फ्यूल सेल या आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है। यह अंतरिक्ष यान प्रणोदन के लिए ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है।

भविष्य में हमारे उद्योग, कृषि, परिवहन, विमानन, घरेलू बिजली और सभी ऊर्जा की आवश्यकताएँ हमारे देश में अक्षय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन से पोषित हों, यही लक्ष्य हमारे देश को विश्व में ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है।

–विनोद जौहरी

ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के लाभ

- जीवाश्म फ्यूल (पेट्रोल, डीजल, कोयला) से कम से कम तीन गुना अच्छा है।
- हाइड्रोजन से कार्बन नहीं निकलता है।
- यह पेट्रोल और डीजल तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष है।
- इसका उपयोग गाड़ियों व रॉकेट के ईंधन में किया जा सकता है।

भविष्य के ईधन में आत्मनिर्भरता

ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बनाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यह भविष्य का प्रमुख ईंधन माना जा रहा है। इसके तहत भारत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे ईंधनों में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। पेट्रोलियम की तरह भारत इन ईंधनों के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। यह भविष्य में फॉसिल फ्यूल (पेट्रोल, डीजल, कोयला) का स्थान लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का

नया वैश्विक केंद्र बनाने के लिए 15 अगस्त 2021 को लाल किले से राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा की। इस मिशन के तहत सरकार भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना चाहती है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में कहा गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स पावर एक्सचेंज से रिन्यूएबल पावर खरीद सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स खुद का भी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत हर साल 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है। इसी के साथ उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भी तय किया। सीएनजी–पीएनजी का नेटवर्क हो, 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हो। भारत इस दिशा में एक तय लक्ष्य के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ भी कदम बढ़ाया है और रेलवे के शत–प्रतिशत विद्युतीकरण के काम में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। इन सारे प्रयासों के साथ ही देश 'मिशन सर्कुलर इकोनॉमी' पर भी बल दे रहा है।

हरित ऊर्जा यानि ग्रीन एनर्जी के लिए भारत के प्रयास लगातार जारी हैं। देश ने फिलहाल कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में 100 गीगावाट का मील का पत्थर पार कर लिया है। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इससे देश में हरित ऊर्जा प्रक्षेपवक्र में तेजी आई है क्योंकि भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता अब 383.73 गीगावॉट हो गई है। इसके अतिरिक्त भारत एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर है– जो वर्ष 2022 के अंत तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता प्राप्त करने, और 2030 तक 450 गीगावाट तक उसे विस्तारित करने पर पूरा होगा। सरकार ने 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है।

हाइड्रोजन पॉलिसी के मुख्य बिन्दु

हाइड्रोजन प्रोडक्शन एप्लीकेशन देने के 15 दिन के अंदर स्वीकृति दी जाएगी। 30 जून 2025 के पहले इसकी शुरूआत करने पर 25 साल तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन ड्यूटी में छूट मिलेगी। हाइड्रोजन मिशन वाली कंपनी 30 दिन तक की रिनुअल एनर्जी को अपने पास रख सकती हैं। हाइड्रोजन मिशन के लिए एक वेबसाइट बनेगी जिसमें इससे संबन्धित सभी काम एक ही जगह पर हो सकेगा। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बनाने वाली कंपनी को निर्यात व शिपिंग के लिए बंदरगाह के पास स्टोरेज के लिए जगह दी जाएगी।

हाइड्रोजन मिशन के ऐलान के बाद कई कंपनियों ने इसे बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

- रिलायंस इंडस्ट्रीज – ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगी इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर भी बनाएगी।
- गेल इंडिया लिमिटेड – नेचुरल गैस में हाइड्रोजन मिला रही है। इसके साथ ही यह देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट लगाने के बारे में योजना बना रही है।
- एनटीपीसी लिमिटेड – विंध्याचल में इसने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसकी प्रति यूनिट उत्पादन लागत यूएसडी 2.8–3/किलो. है।
- आईओसी – मथुरा रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन बना रही है।
- एलएंडटी – हजीरा कॉम्प्लेक्स में इसके प्लांट है। वहीं इलेक्ट्रोलाइजर भी बनाने की योजना है।

आज जी–20 देशों के समूह में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जो अपने जलवायु के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने इस दशक के अंत तक रिन्यूएबल एनर्जी के 450 गीगावाट का लक्ष्य तय किया है। इसमें से 100 गीगावाट के लक्ष्य को भारत ने तय समय से पहले प्राप्त भी कर लिया है। हमारे ये प्रयास दुनिया को भी एक विश्वास दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर 'अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस' इसका बड़ा उदाहरण है।

अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस

पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप–21) के 21वें सत्र के दौरान 121 सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और सौर ऊर्जा संयंत्रों की तैनाती के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का निवेश जुटाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद द्वारा नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ऐसे सौर संसाधन संपन्न देशों का एक गठबंधन है, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों को बढ़ाना, स्वैच्छिक आधार पर शुरू किए गए कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से समन्वित कार्यवाही करना और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना है।

स्वदेशी जागरण मंच के ग्वालियर में 24–26 दिसंबर 2021 को आयोजित राष्ट्रीय सभा में ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन और ओज़ोन पर्त के क्षरण पर चिंतन किया तथा प्रस्ताव पारित किया गया। भविष्य में हमारे उद्योग, कृषि, परिवहन, विमानन, घरेलू बिजली और सभी ऊर्जा की आवश्यकताएँ हमारे देश में अक्षय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन से पोषित हों, यही लक्ष्य हमारे देश को विश्व में ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है। ❑❑

विनोद जौहरीः सह विचार प्रमुख, स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत

चिकित्सा शिक्षा में आत्मनिर्भरता की दरकार

रूस द्वारा यूक्रेन पर युद्ध करने के बाद जब यूक्रेन में फंसे भारतीयों की बात सामने आई तो एक बात जिसकी जानकारी सरकार और कुछ अन्य लोगों को थी, लेकिन आम समाज इस बात से अनभिज्ञ था कि यूक्रेन में 20 हजार भारतीय विद्यार्थी रह रहे थे, जिसमें हजार मेडिकल विद्यार्थी थे। यूक्रेन अकेला देश नहीं है जहां भारतीय विद्यार्थी मेडिकल की शिक्षा के लिए जाते रहे हैं। इसके अलावा चीन, रूस, किर्गीस्तान, फिलिपिन्स और कजाकिस्तान में भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी मेडिकल की शिक्षा हेतु जाते हैं। गौरतलब है कि वहां से एमबीबीए डिग्री हासिल करने के बाद इन विद्यार्थियों को भारत में एक परीक्षा से गुजरना होता है जिसका नाम है फोरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इक्जामिनेशन (एफएमजीई), जिसे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्नामिनेशन द्वारा करवाया जाता है। विडंबना यह है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत अभी तक 10.4 प्रतिशत से 18.9 प्रतिशत तक ही रहा है। यदि पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो यह प्रतिशत औसतन 15.82 प्रतिशत रहा। पिछले 5 वर्षों में इस परीक्षा में भाग लेने वालों की संख्या में तीन गुणा वृद्धि हुई है। 2015 में जहां 12116 विद्यार्थी इस परीक्षा में उतरे, 2020 में यह संख्या 35774 तक पहुंच गई थी। वर्ष 2021 में कोरोना के प्रकोप के चलते यह संख्या 23349 रही।

क्यों जाते हैं विदेश ये मेडिकल विद्यार्थी?

वर्ष 2021 में आयोजित एमबीबीएस हेतु नीट की परीक्षा में 16 लाख विद्यार्थी उतरे, जबकि देश में कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या मात्र 83 हजार थी। इस बात में कोई संदेह नहीं कि देश में मेडिकल डॉक्टरों की भारी जरूरत है। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों को देखा जाए तो हर 1000 व्यक्ति के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए, यानि हमें कुल 13,08,000 डॉक्टरों की जरूरत है, जबकि देश में अभी भी सिर्फ 12 लाख पंजीकृत चिकित्सा कर्मी है। माना जा सकता है कि अभी भी देश में 1,08,000 डॉक्टरों की कमी है। ऐसा नहीं कि देश में मेडिकल सीटों में वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2014 में जहां मेडिकल सीटों की संख्या मात्र 54358 थी, अब तक बढ़कर वह 88120 तक पहुंच गई है। विडंबना यह है कि इनमें से लगभग आधी सीटें सरकारी कॉलेजों में हैं और शेष निजी कॉलेजों में। इन निजी कॉलेजों में 4.5 साल के कुल एमबीबीएस शिक्षा हेतु हालांकि 50 लाख से डेढ़ करोड़ रूपए तक की फीस वसूली जाती है, उनमें भी प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को अत्यंत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हाल ही तक अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया अत्यंत अपरादर्शी और भ्रष्टाचार युक्त थी। माना जा रहा है कि नीट परीक्षा होने के बाद मेडिकल में प्रवेश में भ्रष्टाचार कम हुआ है।

मेडिकल शिक्षा में आत्मनिर्भरता हेतु आज निजी और सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों, व्यापारिक घरानों और अन्य उद्यमियों के लिए यह एक अवसर भी है और चुनौती भी।
– स्वदेशी संवाद

हालांकि मेडिकल प्रवेश परीक्षा अब पहले से अधिक पारदर्शी हो गई है और इसमें भ्रष्टाचार भी काफी कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सच्चाई यह है कि देश में जितने

विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, एमबीबीएस सीटों में काफी वृद्धि होने के बावजूद भी, उनमें से 5 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही प्रवेश प्राप्त हो पाता है। यही नहीं निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई अत्यंत खर्चीली है, हालांकि सरकारी संस्थाओं में यह 20 हजार से 7.5 लाख रूपए है। देश में एमबीबीएस सीटों की कमी और निजी क्षेत्र में महंगी पढ़ाई के चलते बहुत बड़ी संख्या में एमबीबीएस पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थी विदेशों में जाकर एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त करते हैं।

रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद वहां भारतीय विद्यार्थियों की बड़ी संख्या के बारे में देश का ध्यान आकर्षित हुआ और यह ध्यान में आया कि यूक्रेन में ही हजारों विद्यार्थी एमबीबीएस की शिक्षा ले रहे हैं, हालांकि कुल भारतीय एमबीबीएस विद्यार्थियों की दृष्टि से यूक्रेन का स्थान दूसरा है, जबकि सबसे अधिक मेडिकल विद्यार्थी (23 हजार) चीन में हैं, रूस में 16500, फिलीपिंस में 15 हजार, क्रिगीस्तान में 10 दस हजार, जार्जिया में 7500, काजिकिस्तान और पौलेंड में क्रमशः 5200 और 4000 भारत के मेडिकल विद्यार्थी हैं। यहां तक कि बंग्लादेश में भी 5200 भारतीय मेडिकल विद्यार्थी गए हुए हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन में पूरे विश्व में कहीं से भी ज्यादा विदेशी विद्यार्थी भारत से ही हैं, जिसमें से लगभग 50 प्रतिशत मेडिकल अथवा संबंधित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

भारत से लगभग एक लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी दुनिया के अलग—अलग मुल्कों में मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी का एमबीबीएस कोर्स के लिए कुल खर्च 25 से 30 लाख रूपए आता है। यानि देखा जाए तो लगभग 5 वर्ष की एमबीबीएस डिग्री के लिए लगभग 25 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। डालरों में यह राशि लगभग 3.5 अरब डालर है। यदि भारत से जाने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए तो देखते हैं कि भारत से 11,33,749 विद्यार्थी दुनिया के दूसरे मुल्क में पढ़ रहे हैं। अलग—अलग प्रकार की शिक्षा पर अलग—अलग खर्च होता है, लेकिन समझा जा सकता है कि यदि भारत से मेडिकल समेत अन्य प्रकार के विद्यार्थियों का पलायन कम किया जा सके तो देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा में खासी बचत हो सकती है।

क्या है समाधान?

एक ओर देश में महँगी मेडिकल की पढ़ाई तो दूसरी ओर योग्य विद्यार्थियों के लिए सीटों की कमी देश से विद्यार्थियों को विदेशों में जाकर पढ़ने को मजबूर कर रही है। विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई का स्तर उसी से समझ में आ जाता है, कि मात्र 16 प्रतिशत से भी कम विद्यार्थी ही देश में फॉरेन मेडिकल ग्रैजूएट एग्जाम (एफएमजीई) की परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाते हैं। इस प्रकार की डिग्री प्राप्त करने के लिए भी देश की 3.5 अरब डॉलर की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बर्बादी भी चिंता बढ़ा रही है।

यूक्रेन युद्ध से कहीं पहले, पिछले वर्ष ही नेशनल मेडिकल कमीशन ने यह घोषणा की थी कि प्राईवेट मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटें विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेजों की फीस पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया ट्वीट भी महत्वपूर्ण है। जिसमें उन्होंने इसी बात को दोहराया है, कि आधी प्राईवेट सीटों को सरकारी कालेजों की फीस पर उपलब्ध कराया जाएगा। स्वाभाविक है कि सरकार के इस कदम से योग्य विद्यार्थी जो धनाभाव के कारण एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर पाते उन्हें राहत तो अवश्य मिलेगी लेकिन भारत से योग्य विद्यार्थियों का मेडिकल की शिक्षा हेतु पलायन और विदेशी मुद्रा की भारी बर्बादी रोकने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोलना और वर्तमान कॉलेजों की सीटों में वृद्धि ही एकमात्र उपाय है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत से बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई पूर्ण कर चिकित्सक अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में चले जाते हैं जिससे देश में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है। भारत में आज भी 596 मेडिकलकॉलेज हैं जहाँ एमबीबीएस की 88120 सीटें हैं।

उधर एमसीआई को भंग करने के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन हो जाने के बाद देश में अतिरिक्त मेडिकल सीटें स्थापित करने की गति में पहले से ही खासी वृद्धि हुई है। पिछले 7 वर्षों में मेडिकल सीटों में हर वर्ष 8 प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि दर्ज हो रही है। इस गति को और ज्यादा तेज करने की जरूरत है। आने वाले समय में और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलना कोई असम्भव कार्य नहीं है। माना जाता है कि एक मेडिकल कॉलेज खोलने में 250 से 500 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

2014 के बाद देश में 209 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, जिसमें अधिकांश प्राईवेट कॉलेज थे। यूक्रेन युद्ध के बाद इस समस्या को समझते हुए जाने माने उद्योगपति आनंद महेंद्रा द्वारा एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा से एक नयी प्रकार की शुरुआत हुई है। इसी प्रकार देश में असंख्य उद्यमी हैं, जो मेडिकल कॉलेज खोलने में सक्षम हैं। नीति निर्माताओं में भी इस संबंध में सोच विकसित हो ही रही है। मेडिकल शिक्षा में आत्मनिर्भरता हेतु आज निजी और सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों, बिजनेस घरानों और अन्य उद्यमियों के लिए यह एक अवसर भी है और चुनौती भी। ❑❑

बढ़ रहा है मिलेट्स (सुपर फूड) का चलन

आजकल सुपर फूड खाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। 'मिलेट्स' जिन्हें मोटा अनाज कहा जाता है जो कभी हमारा मुख्य अनाज हुआ करता था, उसे धीरे–धीरे करके भुला दिया गया है। ये अनाज अति प्राचीन है जिनका उल्लेख पुरानी सभ्यता व यर्जुवेद में भी मिलता है। ये अभी सुपर फूड बना हुआ। जी हाँ मोटा अनाज जिन्हें मिलेट्स, छोटे आकार के बीज, पोषक अनाज व कदन्न भी कहा जाता है, इन्हें हमें अपनी रसोई व थाली में फिर से लाना है।

मोटे अनाज का महत्व समझकर भारत सरकार ने 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को एक प्रस्ताव दिया था जिसे मार्च 2021 में सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया है, जिसके तहत वर्ष 2023 को ''अन्तर्राष्ट्रीय मोटा अनाज'' वर्ष घोषित किया गया इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया व सर्वसम्मिति से इसे पारित किया। इस साझेदारी के तहत मोटे अनाज पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और ज्ञान के आदान–प्रदान में भारत के नेतृत्व को समर्थन दिया जाना है। इसका उद्देश्य मोटे अनाज के पोषण व स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने के साथ–साथ इन पोषक अनाजों की खेती व खपत को बढ़ावा देना है। इससे खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए भोजन में इन अनाजों को अपनाने के प्रति वैश्विक जागरूकता को भी बढ़ावा देना है। यह अनाज कम पानी में, गर्म स्थान में भी अच्छी तरह उगाये जा सकते है। यह अधिक उत्पादन वाली फसलें है जो कम समय में ही तैयार हो जाती है व साथ ही साथ कीट–पंतगों के प्रति प्रतिरोधक भी है व खाद की कम आवश्यकता वाली फसलें है।

मोटे अनाजों को सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर अनाज के रूप में जाना जाता है। ये दो प्रकार के होते है–

1. मोटे दाने वाला जिसमें – 1 बाजरा, 2. रागी, 3 ज्वार, 4 कगंनी, 5 पुनर्वा / चना, 6. टेफ या फेनिओं आदि।

2 छोटे दाने वाला, जिसमें – 1 सावां, 2 कोदो, 3 कुटकी।

यह सभी मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर है। इनमें अन्य अनाजों के मुकाबले अधिक प्रोटीन पाया जाता है, साथ ही एक जरूरी अमीनो एसीड लाइसिन जो गेंहूँ में अनुपस्थित रहता है, वह भी पाया जाता है। लाइसिन की उपस्थिति मांसपेशियों के क्षरण को रोकती है व शरीर को छरहरा बनाये रखने में मदद करती है। इनके उपयोग से सेरोटोनिन की मात्रा स्रावित होती है जो इसके रक्त स्तर का बढ़ाकर शरीर को तनावमुक्त रखने में मदद करता है। इनमें रेशा अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह कब्ज व आंत से संबंधित अन्य विकारो के लिए उपयुक्त है। कगंनी में दोनो तरह के रेशे घुलनशील व अघुलनशील भी उपस्थित रहतें है। इसके साथ ही फाइटोन्यूट्रिन्ट भी पाए जाते है जो आंत के कैंसर के खतरे को कम करने वाला माना गया है। रेशे की मात्रा अधिक होने से इनका पाचन धीमा होता है व कार्बोज शर्करा धीरे–धीरे रक्त में पहुँचती है। ये अनाज विशेषकर रागी, बाजरा, कगंनी आदि मधुमेह रोगियों के लिए वरदान है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक सूचकांक कम होता है। यानि रक्त शर्करा के स्तर पर कार्बोज के प्रभाव का माप यानि जो कार्बोज पाचन के दौरान तेजी से टूटते है और रक्त धारा में ग्लूकोज को तेजी से छोड़ते है उनका ग्लाइसेमिक सूचकांक ज्यादा होता है और जो धीरे–धीरे टूटते है उनका ग्लाइसेमिक सूचकांक कम होता है। निम्न ग्लाइसेमिक सूचकांक कार्बोज के पाचन व अवशोषण की धीमी दर को इंगित करता है यह रक्त शर्करा को कम करने व इंसुलिन के प्रभाव को बढ़ाता है। रेशा पाचन की

भारत से मोटा अनाज खरीदकर विदेशी कंपनियां उत्पाद बनाकर उन्हें भारत सहित दुनियाभर में बेच मुनाफा कमा रही है।

– **शीला शर्मा**

गति को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण यानि आंत में उपस्थित सूक्ष्मजीवों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, पेट भरने की अनुभूति देता है, जिससे पेट जल्दी खाली नहीं होता व भूख जल्दी नहीं लगती। इस प्रकार यह वजन को नियंत्रित व कम करने में बेहद उपयोगी है। यह रेशा आंत साफ रखने, विषैले पदार्थो को बाहर निकालने, पाचन से संबंधी विकारों के लिए अमृततुल्य है।

कदन्न ग्लूटेन फ्री होते है। इस तरह यह सिलिएक बीमारी या गेंहूँ से एलर्जी वालों के लिए व कई बार मानसिक विकास के विकारों के लिए जिन्हें ग्लूटेन रहित भोजन दिया जाना रहता है वे इन अनाजों को आराम से अपने भोजन का हिस्सा बना सकते है। बाजरा में उपस्थित लिगनिन जो कि एक प्रतिरोधी तत्व है यह आंत में परिवर्तित होकर स्तन कैंसर से बचाता है या यह कह सकते है कि इनके उपयोग से स्तन कैंसर के बनने का खतरा 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है, इस तरह यह महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी है। मैग्नीशियम की अधिकता की वजह से यह महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान होने वाले असहनीय दर्द एवं ऐंढन को कम करता है।

गर्भवती व धात्री माताओं को इनके सेवन विशेषकर रागी की सलाह दी जाती है क्योंकि यह कैल्शियम का अच्छा स्त्रोत है इसके सेवन से दूध का स्त्राव अधिक होता है जिससे माताएं अपने नवजात को अधिक समय तक दूध पिला सकती हैं। यह दूध बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों में गिना जाता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर पाए जाते हैं जो शरीर में उपस्थित फ्री रेडिकल से मुकाबला करते हैं उनके प्रभाव को कम करके बढ़ती उम्र के असर को कम करते हैं। त्वचा के निर्माण कारक कोलेजन को भी बनाते हैं जो त्वचा का लचीलापन बढ़ा कर झुर्रियों को कम करते हैं। ज्वार, कोदो, कुटकी में विशेष रुप से एंटीऑक्सीडेंट की अधिक मात्रा इन्हें विशिष्ट बनाती है यह मात्रा अन्य फल व अनाजों के मुकाबले अधिक एंटीऑक्सीडेंट प्रतिक्रिया देती है। इनके उपयोग से कुल कोलेस्ट्रॉल व बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होकर अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। ज्वार में उपस्थित फायटोकेमिकल मनुष्य के शरीर व स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालते हैं अंदर जाकर अन्य अनाज फलों से अधिक एंटीऑक्सीडेंट प्रतिक्रिया देते हैं। इनका उपयोग हृदय के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है व रक्त के मुक्त प्रवाह में मददकारी है। रक्तचाप को नियंत्रित करके कम करते हैं वह हृदय रोग के खतरे को घटाते हैं।

रागी में खनिज तत्व की अधिकता विशेष है। इनके नियमित उपयोग से कैल्शियम लोह तत्व की कमी दूर होती है, विशेषकर बढ़ते बच्चों के लिए गुणकारी है यह खून की कमी को दूर कर हड्डियों के विकास में मदद करता है नियमित उपयोग से कुपोषण, अपक्षीय बीमारियों से बचा जा सकता है। बढ़ते शिशुओं के लिए इनका उपयोग पूरक आहार के रूप में किया जाता है।

मोटे अनाजों से एमायलेज–यानि भोजन पचाने वाला एंजाइम से भरपूर भोजन बनाया जा सकता है, जो कम घनत्व में अधिक ऊर्जा प्रदान करते है जिन्हें आंत से संबंधित विकार या पाचन विकार है, नली द्वारा आहार दिया जाना है यह आसानी से दिये जा सकते है। मोटे अनाज गहरी व शांतिप्रद निंदा में सहायक होते हैं

भोजन में शामिल करने हेतु सुझाव–

1 शुरू में एक समय के भोजन में इन्हें शामिल करें।
2 चावल की जगह मोटा अनाज उपयोग करें जैसे खिचड़ी, चीला, इडली, डोसा आदि में 1:1 के अनुपात में उपयोग करें।
3 मोटे अनाज व सब्जियों का मिश्रित उपयोग करें स्वादिष्ट पुलाव, सब्जी वाली नमकीन खिचड़ी, दलिया बनाएं, उपमा आदि बनाएं इनमें दालें भी मिलाई जा सकती हैं।
4 अंकुरित करके इनके पोषण को बढ़ाया जा सकता है।
5 पायसम खीर, चूरमा आदि बनाकर मीठे के रूप में खाया जा सकता है।
6 रोटी, पराठा, बाटी बनाकर उपयोग किया जा सकता है।
7 नाश्ते में ओट्स या कार्नफ्लैक्स के बदले इन्हें खाया जा सकता है।
8 मठरी, चीला, खाखरा, पीड़िया, पीठा, ढोकला खम्मन आदि बनाया जा सकता है।
9 सूप में सब्जी के रस आदि में मिलाया जा सकता है।

इनके अलावा और भी अपने बुद्धि विवेक से नये प्रयोग में स्वादिष्ट व्यंजन बनाये जा सकते है।

भारत अकेले दुनियाभर में 38 प्रतिशत मोटा अनाज पैदा करता है। बेबी फूड, रेडी टू ईट, ब्रेक फास्ट, बेकरी, रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व, बेवरेज व पशु आहार बनाकर चीन मोटी कमाई कर रहा है, जबकि 9 प्रतिशत पैदावर करता है। भारत से मोटा अनाज खरीदकर विदेशी कंपनियां उत्पाद बनाकर उन्हें भारत सहित दुनियाभर में बेच मुनाफा कमा रही है। 11388 मिट्रिक टन मोटा अनाज पैदा करके भी कमाई में भारत चीन से काफी पीछे है। कारण प्रोसिसींग यूनिट बहुत कम है। देश में स्नैक्स, इडली, डोसा, उपमा, बाजरे के लड्डू, चूरमा, कुकीज आदि उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से पैकिंग नहीं होने के कारण व ब्रॉडिंग न होने का खामियाजा देश को उठाना पडता है। रोजगार सृजन व स्वावलंबी भारत अभियान में इस विषय पर युवाओं को ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।❑❑

शीला शर्मा: आहार विशेषज्ञ, अखिल भारतीय सह महिला प्रमुख, स्वदेशी जागरण मंच, रायपुर (छ.ग.)

समृद्ध खेती से ही पंजाब का स्थाई विकास

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब में लोगों को सबकुछ मुफ्त का पहाड़ा पढ़ाकर फौरी तौर पर मत तो हासिल कर लिया है, लेकिन अब जबकि पंजाब के लोगों ने निर्णायक जनादेश दे दिया है, बाटने का दावा करने वालों की भी जमीन खिसकती नजर आ रही है। दरअसल पंजाब में बदलाव का जो फैसला आया है और अपने साथ जिस तरह की चुनौतियां लाया है, वे नई सरकार के लिए बहुत बड़ी हैं। लोगों की अपेक्षाएं काफी ज्यादा हैं और पंजाब की आर्थिकी जिस कदर खस्ताहाल है, इससे इंकार नहीं कि आगे राह अत्यंत कठिन है। अगली राह परंपरागत कार्यशैली से हरगिज़ नहीं पूरी होगी। परंपरागत कृषि संसाधनों को विकसित किए बगैर पंजाब की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती।

जिस सामाजिक–आर्थिक संकट के बोझ तले आज पंजाब दबा हुआ है, वो पिछले तीन दशकों के कुशासन का परिणाम ज्यादा है, इससे उबरने की भरोसेमंद राह को नई आर्थिक रूपरेखा की दरकार है। यह प्राप्ति केवल नए उद्योगों की स्थापना और व्यापार को विस्तार देने के लिए निवेश की चाह रखकर नहीं हो पाएगी। जब सब ओर उद्योगों में नई जान फूंकने और उद्योग–मित्र नीतियां बनाने की जोरदार मांग उठी हुई है, ऐसे में पंजाब को अपनी अर्थव्यवस्था की तरक्की के लिए 'डंबल इंजन अर्थव्यवस्था' के सिद्धांत अपनाकर पुनर्संरचना करने की बेतरह जरूरत है। इसके तहत उद्योगों को पुनर्जीवन देना और ठीक उसी समय कृषि में प्राण फूंकने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

यहां 'डबल इंजन' की सरकार का मतलब वह राजनीतिक नारा नहीं है जिसका अर्थ केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होता है। यह 'डबल–इंजन' अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण पहियों–उद्योग और कृषि–को एक समान गति देने वाला है ताकि अर्थव्यवस्था की नई किंतु स्थाई नींव बन सके। जहां पिछले सालों के दौरान आर्थिक सुधारों का ध्यान पूर्वतः उद्योगों पर केंद्रित रहा है वहीं खेती की अनदेखी ने कृषि संकटों को और बढ़ाया है। इसका

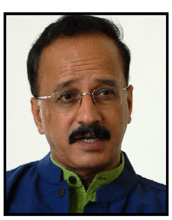

परंपरागत कृषि संसाधनों को विकसित किए बगैर पंजाब की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती।
–देविन्दर शर्मा

असर जितना भारत का अन्न भंडार कहे जाने वाले पंजाब पर हुआ है उतना और कहीं नहीं। प्रति हेक्टेयर 11 टन अनाज उगाने की क्षमता पाकर जो विश्व के उच्चतम उत्पादनों में एक है, इसके बावजूद पिछले सालों में किसानों पर कृषि ऋण बढ़ता गया। इसके अलावा पंजाब प्रांत किसानों द्वारा आत्महत्या के मुख्य स्थान में तब्दील हो गया।

नई दिल्ली की सीमा पर चले किसान आंदोलन का स्पष्ट संदेश है कि किसानों ने आर्थिक नीति में प्रणालीगत बदलाव लाने की जो मांग की है, कहीं वह हालिया विधानसभा चुनाव के शोर–शराबे में खो न जाए। उद्योगों की एवज में कृषि की बलि देने की बजाय जरूरत है खेती के धंधे में नई जान डालने और इसको अर्थव्यवस्था का दूसरा पहिया समझने की।

केवल कृषि में वह दम है जो अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाए, बशर्ते हम खंडित हुई खाद्य प्रणाली को फिर से जोड़ दें। एक जीवंत कृषि लोगों को फायदेमंद रोजगार देने की क्षमता रखती है और शहरों में नौकरियां पैदा करने को सरकारों पर जो दबाव रहता है उसे घटा सकती है।

पंजाब में कृषि–योग्य भूमि का 98.5 फीसदी क्षेत्र निश्चित सिंचाई के अंतर्गत होना व वृहद कृषि विपणन तंत्र, जिसमें गांवों तक संपर्क मार्ग शामिल हैं, ग्रामीण रूपांतरण के लिए यह मजबूत नींव पहले से मौजूद है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने की ओर पहलकदमी कर दी है, इस सूची में खेती को शामिल करने और इसको गैर–कृषि गतिविधियों से जोड़ने पर यह काम अर्थव्यवस्था को गति में उत्प्रेरक खुराक की तरह बन जाएगा।

शुरुआत के लिए, सघन कृषि से पर्यावरण पर पड़ा बहुत बड़ा असर, जैसे कि मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट,

केवल कृषि में वह दम है जो अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाए, बशर्ते हम खंडित हुई खाद्य प्रणाली को फिर से जोड़ दें। एक जीवंत कृषि लोगों को फायदेमंद रोजगार देने की क्षमता रखती है और शहरों में नौकरियां पैदा करने को सरकारों पर जो दबाव रहता है उसे घटा सकती है।

भूमिगत जल ह्लास, पराली जलाने पर प्रदूषण और जीवनशैली जनित बीमारियां शामिल हैं, इनसे निजात पाने के लिए पंजाब को 'सदाबहार क्रांति' की ओर बढ़ने की जरूरत है। अवश्य ही ताकतवर लॉबियां दिग्भ्रमित करने वाले तमाम प्रलयंकारी नुस्खे नई सरकार को भी सुझाएंगी किंतु तगड़ी राजनीतिक इच्छाशक्ति द्वारा उनको दरकिनार करके पंजाब को 'सदाबहार क्रांति' का ध्वजवाहक बनाया जा सकता है। इसके लिए अनुसंधान और शिक्षा पाठ्यक्रमों में यथेष्ट बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी और साथ ही कृषि संबंधी विस्तारित गतिविधियों की पुर्नसंरचना करने की भी। इसमें पर्यावरणीय सेवा दृष्टिकोण का समावेश भी हो, यह वह सिद्धांत है, जो प्राकृतिक स्रोत बचाने वाले किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन आय प्रदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य व्यवस्था शिखर सम्मेलन 2021 के वैज्ञानिक समूह के मुताबिक, खाद्यान्न उगाने की असल कीमत उपभोक्ता द्वारा अदा किए जाने वाले मूल्य से लगभग तीन गुणा ज्यादा है। इसके हानिकारक असर को समझे बगैर ज्यादातर समाज को इसकी असल कीमत पर्यावरणीय और स्वास्थ्य के नुकसान के रूप में चुकानी पड़ती है। अन्न पैदा करने की एवज में पर्यावरणीय ह्रास, खासकर पंजाब जैसे क्षेत्र में, जो फसल पैदा करने के लिए रसायनों पर काफी निर्भर है, इसको घटाना होगा।

फसल विविधता को लेकर किसानों से गेहूं–चावल चक्र से परे हटने की उम्मीद की जाती है, विकल्प में जो फसलें सुझाई जाती हैं उनका न्यूनतम खरीद मूल्य न होना और मददगार विपणन तंत्र का अभाव अड़चन है। केरल के उदाहरण से सीख लेकर, जहां राज्य सरकार ने उत्पादक को लागत पर 20 प्रतिशत लाभ देने हेतु 16 सब्जियों एवं फलों के लिए न्यूनतम क्रय मूल्य का भरोसा दिया है,इससे नीचे कीमत गिरने पर सरकार दखल देकर भरपाई करती है, यह समीकरण पंजाब में भी लागू किया जाना चाहिए। इस मद में पंजाब को शुरुआत में 250 करोड़ का इंतजाम करना होगा। इसके अलावा, दिल्ली में मदर डेयरी के विशाल दूध नेटवर्क की तर्ज पर पंजाब भी अपने खुदरा सब्जी विक्रेता केंद्र बना सकता है। इसी तरह तिलहन, दलहन, मोटा अनाज़ और तेल–बीजों के लिए भी योजना बन सकती है।

कृषि सुधार तब तक व्यवहार्य नहीं होगा जब तक कि पंजाब पहले 'किसान–आय एवं भलाई आयोग' की स्थापना न करे, जिसके अधिकार क्षेत्र में एक शक्ति खेती से न्यूनतम मासिक आय सुनिश्चित करने की हो और यह 25000 रुपये मासिक से कम न हो। यदि कृषि को आर्थिक रूप से व्यावहारिक और टिकाऊ बनाना है, तो ऐसी कोई वजह नहीं लगती कि पंजाब 'डबल इंजन' आर्थिक दृष्टिकोण अपनाकर नई आर्थिक क्रांति का अग्रदूत न बन पाए। ❑❑

लेखक कृषि एवं खाद्य मामलों के विशेषज्ञ हैं।

पेड़ों के संरक्षण से ही सुधरेगा पर्यावरण

कोरोना काल ने प्रकृति के महत्व को बहुत ही गहराई से हमें समझा दिया है। कोरोना महामारी की लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण न जाने कितने लोग असमय काल–कवलित हो गये। गौरतलब है कि पृथ्वी पर पेड़–पौधे ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्त्रोत हैं और इनकी प्रचुरता स्वस्थ वातावरण का निर्माण करती है। पेड़–पौधों की पत्तियों से ऑक्सीजन तैयार होती है, जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्बनडाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन का विसर्जन।

पर्यावरण संकट के जितने भी कारण देखने को मिलते हैं, उनके मूल में पेड़ों की निर्मम कटाई है। धरती कभी वनों से ढ़की रहती थी, आज उजाड़ हो गयी है। वनों का सफाया हो जाने से बाढ़, सुखा व महामारी के खतरों में वृद्धि हो रही है। पेड़ों के विनाश के चलते धरती रेगिस्तान में तब्दील होती जा रही है, जिससे उसका तापमान निरन्तर बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी के जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। धरती और उस पर खड़े पहाड़ों की लगातार पाताल तोड़ खुदाई से धरती असन्तुलित होती जा रही है, जो कभी भी कहीं भी लोगों की जिन्दा समाधी बन सकती हैं। प्रतिदिन हजारों टन विषैली गैसों को अवशोषित करके ऑक्सीजन में उत्सर्जित करने वाले पेड़ों का तेजी से सफाया हो जाने से वायुमण्डल में गैसों का संतुलन बिगड़ गया है। विभिन्न स्त्रोतों से निकलने वाली यह जहरीली गैस बगैर अवशोषित हुए वायुमण्डल में पहुँच रही है, जिससे लोग तरह–तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए जलवायु परिवर्तन के कानूनों, नीतियों और पेड़ों की रक्षा के प्रेरक प्रसंगों को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में उचित स्थान दिया जाए, जिससे कि पर्यावरण के बारे में युवा पीढ़ी को उचित ज्ञान व प्रेरणा प्राप्त हो सके।

– राजेन्द्र शर्मा

पौराणिक काल में मनुष्य दीर्घकालीन जीवन व्यतीत करता था, उसका मूल कारण पर्यावरण का शुद्ध होना था। आज हम अशुद्ध वातावरण में जी रहे हैं, जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं, जहर सूंघ रहे हैं, ऐसे जहरीले वातावरण में जीने से मनुष्य की औसत आयु दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, यह सब प्रकृति से विकृति की ओर जाने का परिणाम है। प्राचीनकाल में मानव सीधा–साधा जीवन व्यतीत करता था लेकिन जब से मानव ने पर्यावरण के साथ अधिक लाभ हेतु छेड़छाड़ प्रारम्भ की और अदूरदर्शिता से प्राकृतिक सम्पदाओं का दोहन किया तभी से वातावरण में अवांछित परिवर्तन हुए।

विज्ञान मानव की सुख सुविधा के लिए है तबाही और बर्बादी के लिए नहीं।

पर्यावरण संकट के लिए सबसे अधिक पश्चिम के देश जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपनी अत्याधुनिक तकनीक को विकसित करने के लिए संसार के वातावरण को प्रदूषित कर दिया है और मनचाहे बम मिसाइल के परीक्षण और युद्धों के माध्यम से वातावरण को विभिन्न प्रकार

की जहरीली गैसों से भर दिया है, जिससे आसमान जगह–जगह से फट गया है तथा ऑजोन पर्त में असंख्य छेद हो गये हैं। अणु–परमाणु बमों की सुलगती भट्टियाँ और मानवघाती युद्ध पर्यावरण की जान के दुश्मन हैं। विकसित देश परिवेश में जरूरत से ज्यादा कार्बनडाइऑक्साइड़ उड़ेलने के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में कटौती नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, और न ही वे उन देशों की आर्थिक मदद करना चाहते हैं जो कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के इच्छुक हैं। पश्चिम के विकसित अमीर लोग पर्यावरण शुद्धिकरण के विश्वव्यापी अभियान के खर्चें का बोझ विकासशील गरीब देशों पर लादकर उन्हें अपने गहने रख रहे हैं ताकि उनके किए का दण्ड भुगतते रहें। गरीब देश भी उनकी एटनोमिक अणु बमों की ताकत के आगे उनकी दादागिरी का माकूल जवाब देने की स्थिति में नहीं है।

विश्व में औद्योगिक क्रांति के कारण प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि सारा वायुमण्डल रेडियोधर्मी पदार्थों तथा विषाक्त गैसों से भर गया है। कल–कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियों, तालाबों, समुद्रों व धरती पर प्रवाहित कर दिए जाने से पानी विषाक्त होता जा रहा है और धरती बंजर। कितने दुर्भाग्य की बात है कि प्रकृति के विनाश के सभी कारण मानवजनित हैं लेकिन उस पर अमल करके क्रियान्वित करने को तैयार नहीं है। मानव जाति अपनी बर्बादी की दास्तान स्वयं लिख रही है।

विश्व के सभी देश बिगड़ते पर्यावरण के प्रति गंभीर एवं सख्त हैं लेकिन बात जब पर्यावरण संतुलन के प्रति ठोस कदमों के क्रियान्वयन की आती है तो आपस में कोई एकजुटता ही नहीं बन पाती। कोई भी देश पर्यावरण के लिए अपने आर्थिक स्वार्थों के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है।

पर्यावरण संबंधी कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत के कई शहर दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु प्रदूषण डाटाबेस के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 15 शहरों में से 14 भारत में हैं। देश की राजधानी दिल्ली की हालत तो गैस चैंबर सरीखी हो गयी है जहाँ स्वस्थ व्यक्ति के लिए साँस लेना भी मुश्किल हो गया है। मेडिकल जर्नल 'दि लेंसेट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण के चलते प्रतिवर्ष दस लाख से ज्यादा लोग मौत के मुँह में समा जाते हैं।

दिल्ली सहित देश के अन्य अत्यधिक प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है तो लोगों को निजी वाहनों का प्रयोग कम कर सार्वजनिक परिवहन को अपनाना होगा तथा बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर हरियाली को बढ़ावा देना होगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायर्नमेंट के अनुसार भारत में 30 प्रतिशत असामयिक मृत्यु दूषित पर्यावरण के कारण होती है। दुनिया के 20 सबसे दूषित शहरों में से 11 भारत के हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में असफल भारत में बीमारी और मृत्यु निरंतर बढ़ रही है। बढ़ते कार्बन और घटती हरियाली के कारण ही आज सारा वातावरण प्रदूषित हो गया है।

असल में देखा जाए तो देश में पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हो क्या रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े–बड़े दावे और वादों के बावजूद वृक्षों के विनाश का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। सरकारें देश के विकास को गति देने के लिए लम्बे–चौड़े एक्सप्रेस–वे बनाने के नाम पर लाखों वृक्षों को काटने का आदेश देने में विलम्ब नहीं कर रही हैं। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों को चौड़ा करने के लिए करीब नौ सौ किलोमीटर के दायरे में वर्षों पुराने लाखों हरे–भरे वृक्ष काट डाले गये। शहरी विकास के नाम पर हिमालय क्षेत्र हो या गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र हर जगह हजारों की संख्या में विशालकाय वृक्ष बड़ी बेरहमी से काटे जा रहे है। यदि विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए सड़कों को चौड़ा करना ही है तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं तलाशा जाना चाहिए, जिससे अधिकांश वृक्षों को बचाते हुए विकास कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। विकास के नाम पर लाखों वृक्षों के विनाश के चलते पर्यावरण सन्तुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में हरे–भरे वृक्षों के विनाश के चलते मानव सहित समस्त प्राणी जगत का जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा, जीवन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो यह विकास किस काम का?

आवश्यकता इस बात की है कि आम जनता जागे और वृक्षों की कटाई रोकने के लिए आगे आए। जब तक आम नागरिक वृक्षों की कटाई रोकने के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक यह बर्बादी रूकने वाली नहीं है। कुछ माह पूर्व दिल्ली में 16500 पेड़ काटे जाने का आदेश सुनाया था किन्तु ''खेजड़ली'' के चिपको आंदोलन की तर्ज पर दिल्लीवासियों ने व्यापक स्तर पर जन–अभियान चलाकर सरकार को अपना निर्णय वापस लेने को विवश कर इन हरे–भरे वृक्षों को कटने से बचा लिया था। ऐसे ही प्रयास पर्यावरण को संरक्षित रख सकेंगे। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए जलवायु परिवर्तन के कानूनों, नीतियों और पेड़ों की रक्षा के प्रेरक प्रसंगों को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में उचित स्थान दिया जाए, जिससे कि पर्यावरण के बारे में युवा पीढ़ी को उचित ज्ञान व प्रेरणा प्राप्त हो सके। ❑❑

ए–661,पंचवटी कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज.)

सीमा–शुल्क पर स्थगन बहुत हानिकारकः एसजेएम

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क का स्थगन जारी रखना विकासशील देशों के हित में न होकर उनके लिए 'बहुत हानिकारक' होगा और भारत को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में आगामी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इसका विरोध करना चाहिए।

स्वदेशी जागरण मंच ने अपने एक आलेख में कहा कि व्यापार के मौजूदा परिदृश्य में यह कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा–शुल्क न लगाना भारत के लिए एक घाटे का सौदा होगा।

मंच ने कहा कि डिजिटल उत्पादों के भौतिक व्यापार की समय के साथ घटती प्रवृत्ति को देखते हुए इस मुद्दे को अब और नजरंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके कारण भारत में शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी आई है।

आलेख में कहा गया, ''आज चौथी औद्योगिकी क्रांति का वक्त है। यह डिजिटल औद्योगिकीकरण के जरिये ही आएगी।''

यह आलेख स्वदेशी जागरण फाउंडेशन ने प्रकाशित किया है और इसे एसजेएम के सह–समन्वयक अश्विनी महाजन और अनिल शर्मा ने लिखा है।

https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/india-should-oppose-continuation-of-moratorium-on-customs-duties-sjm/articleshow/90750325.cms

स्वरोजगार से दूर होगी युवाओं की बेरोजगारी

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा हिंदू नव वर्ष के अवसर पर ग्राम पोचानेर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी एवं स्थानीय ग्रामीण

लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में परंपरागत रोजगार करने वाले लोगों को स्मृति चिन्ह एवं भगवा वस्त्र से सम्मान किया है।

मुख्य वक्ता क्षेत्रीय संयोजक अरुषेन्द्र शर्मा ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश का लघु उद्योग कुटीर उद्योग एवं परंपरागत व्यवसाय लोगों की जीविका के साधन थे। उस समय हमारे देश में बेरोजगारी नाम का कोई शब्द नहीं था, हर व्यक्ति रोजगार युक्त था आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्याएं हैं। यदि हम नौकरी को नहीं परम्परागत रोजगार को महत्व देंगे तो हम सब मिलकर हमारी पीढ़ी को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। स्वरोजगार से ही बेरोजगारी हो दूर हो सकती है। कार्यक्रम की भूमिका प्रांत संयोजक डॉ. हरिओम वर्मा ने रखते हुए बताया कि हमे समाज के उन लोगों का सम्मान करना जरूरी है जिन्होंने अपने जीवन के लिए स्वयं के रोजगार को स्थापित किया। विशेष अतिथि के रुप में उपस्थित राहुल विश्वकर्मा ने स्थानीय लोगों को स्वदेशी गीत सुनाकर अपनी बात रखी।

अध्यक्षता सरपंच धनसिंह परमार ने की व संचालन हरिओम हिंदुस्तानी ने किया। अंत में आभार मानसिंह परमार ने माना। धनसिंह राजपूत, अशोक पांचाल मुकेश पांचाल, हेमंत जयसवाल, सुरेंद्र डोडिया आदि उपस्थित थे।

https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/shajapur-selfemployment-of-youth-will-remove-unemployment-7431096

टेनसेंट के मालिक पोनी मा भारत में बीजीएमआई/पबजी प्रतिबंध विवाद में फंसे

भारत में पबजी/बीजीएमआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर चल रहे विवाद में शामिल चीनी अरबपति पोनी मा पर शिकंजा कसता जा रहा है।

प्रहार नामक एनजीओ ने नशे की लत जैसे खेल बीजीएमआई पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था। इस एनजीओ को स्वदेशी जागरण मंच ने समर्थन दिया था। इसने चीनी तकनीकी दिग्गज टेनसेंट के मालिक पोनी मा को एक खुला पत्र दिया है। पत्र में, एनजीओ ने पोनी मा को चुनौती दी है कि वह बीजीएमआई के पीछे कंपनी क्राफ्टन में अपनी पूरी हिस्सेदारी का खुलासा करने के लिए कहें।

पत्र में, एनजीओ ने कहा, आपका विशाल साम्राज्य दुनिया भर में फैला हुआ है और आप विशेष रूप से गेमिंग कंपनियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी लेने और चुपके से उन पर शासन करने की अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं। इन कठपुतली कंपनियों को दुनिया भर में किसी को भी दरकिनार करने के लिए जाना जाता है।

प्रहार ने पहले गृह मंत्री और आईटी मंत्री को पत्र

लिखकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत बीजीएमआई पर प्रतिबंध लगाने का आहवान किया था, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है।

अपने लेटेस्ट सैल्वो में, एनजीओ ने पोनी मा को दस सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें क्राफ्टन के वास्तविक स्वामित्व, टेनसेंट और क्राफ्टन के बीच गहरे संबंध और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के बारे में कई सवालों के जवाब मांगे गए हैं। खेल की उत्पत्ति पर, प्रहार ने पूछा, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पबजी मोबाइल (भारत में बीजीएमआई कहा जाता है) को सबसे पहले लाइटस्पीड एंड क्वोन्टम द्वारा विकसित किया गया था जो कि टेनसेंट का एक आंतरिक विभाजन है?

आगे यह सामने आया कि टेनसेंट का गेम फॉर पीस क्राफ्टन द्वारा विकसित किया गया था और यह चीनी वायु सेना पर केंद्रित पबजी की प्रतिकृति है। इसने पोनी मा को इस तथ्य से इनकार करने के लिए कहा कि पबजी, बीजीएमआई और गेम फॉर पीस में एक ही मूल गेमप्ले, ग्राफिक डिजाइन, वर्ण हैं और सभी तीन गेम अनिवार्य रूप से कॉस्मेटिक परिवर्तनों के साथ नियामक अधिकारियों को धोखा देने के लिए बनाये हैं।

नवंबर 2021 में रिसर्च फर्म सेंसर टॉवर के अनुसार, पबजी/गेम फॉर पीस, टेनसेंट का सबसे अधिक बिकने वाला मोबाइल गेम है, जिसमें ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर आजीवन खिलाड़ी खर्च करते हैं।

एनजीओ ने पोनी मा को पाकिस्तान में पबजी मोबाइल के साथ टेनसेंट के जुड़ाव से इनकार करने के लिए भी कहा। टेनसेंट गेम्स पाकिस्तान में पबजी मोबाइल का प्रकाशन और संचालन जारी रखता है। यह पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) की फ्रेंचाइजी लाहौर कलंदर्स का प्रायोजक भी है।

एनजीओ ने आगे कहा कि जबकि टेनसेंट के पास क्राफ्टन में सीधे तौर पर 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है, यह अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है और उसने पोनी मा को कंपनी में अपनी पूरी अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी का पारदर्शी रूप से खुलासा करने के लिए कहा है।

इसने आगे चीनी अरबपति से जवाब देने के लिए कहा कि क्या 2020 में, टोरंटो विश्वविद्यालय के एक शोध केंद्र सिटीजन लैब ने कहा कि टेनसेंट चीनी सरकार की सेंसरशिप में मदद करने के लिए अपने मैसेजिंग ऐप वीचैट पर विदेशी यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई सामग्री का सर्वेक्षण कर रहा है।

प्रहार ने अपने पत्र में मा से यह भी पूछा, बीजीएमआई की गोपनीयता नीति स्पष्ट रूप से उपयोगकर्ता डेटा को तीसरे पक्ष के साथ साझा करने की अनुमति देती है, जिनके समाधान खेल में उपयोग किए जाते हैं। क्या यह सच है कि बीजीएमआई टेनसेंट से संबद्ध संस्थाओं से तीसरे पक्ष के समाधान का उपयोग करता है?

पूर्व में स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने सरकार से विवादास्पद बीजीएमआई–पबजी एप के पूर्ववृत्त और चीन के प्रभाव की पूरी तरह से जांच करने का आग्रह किया था।

https://www.newsnationtv.com/science-tech/news/the-recluive-chinee-billionaire-pony-ma-260209.html

'हानिप्रद चीजों पर हो सीधी चेतावनी, स्टार रेटिंग नहीं': स्वजामं

नुकसानदेह खाने–पीने की चीजों पर सीधी चेतावनी छापने की बजाए स्टार रेटिंग की व्यवस्था लागू करने की तैयारी का स्वदेशी जागरण मंच ने विरोध किया है। मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि फैंसला करते समय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का ध्यान लोगों के स्वास्थ्य पर होना चाहिए, न कि कंपनियों के मुनाफे पर।

महाजन ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय को अपने स्तर पर पहल करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली खाने–पीने की चीजों पर स्टार रेटिंग जैसी भ्रमित करने वाली व्यवस्था नहीं हो। बल्कि सीधे–सीधे चेतावनी देकर बताया जाए कि उसमें वसा, चीनी या नमक ज्यादा है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने इस संबंध में फैसला करने के लिए जो बैठकें की है, उनमें इतनी बड़ी संख्या में

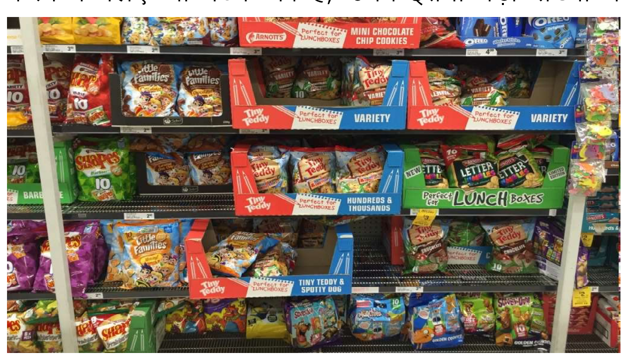

इन्हीं कंपनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति फैसले की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करती है। इन कंपनियों के साथ प्राधिकरण की पुरानी साझेदारी भी है। ये कंपनियां वसा, चीनी और नमक का अत्यधिक उपयोग कर ग्राहकों को अपने उत्पादों की लत लगाती है। इनका खासतौर पर निशाना बच्चे होते हैं। देश में मधुमेह, ब्लडप्रेशर, किड़नी और लीवर की बीमारियां खाने में चीनी, नमक और वसा के आधिक्य के कारण हो रहे हैं। पैकेट पर कोई चेतावनी नहीं होने के कारण लोग अनजाने में इन हानिकारण खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं।

स्थानीय विक्रेताओं से सामान खरीद राष्ट्र को मजबूत करें

स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत पूर्वी विभाग की ओर से होली त्यौहार के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसमें आए देश भर से चुनिंदा व प्रतिष्ठित कवियों ने देशहित मे लिखी अपनी कविताओं से सम्मेलन में आए लोगों को प्रेरित किया। सम्मेलन में मुख्य तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य दयानंद, भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन शर्मा, दिल्ली भाजपा महामंत्री व एनडीएमसी सदस्य कुलजीत सिंह चहल शामिल हुए।

सभी ने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा देश को सशक्त बनाने की ओर किए जा रहे कार्यों की सराहना की। दयानंद का कहना था कि जहां होली हमारे देश की संस्कृति को दर्शाता है वहीं होली का त्योहार वैर–विरोध छोड़ आपसी मिलन का प्रतीक है। दयानंद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार होली को लेकर अच्छा माहौल रहा। लोगों ने दो साल बाद ठीक ढंग से होली मनाई। इसके लिए जमकर खरीदारी की। लोगों ने होली के त्योहारों के लिए स्थानीय खुदरा दुकानदारों से सामान खरीदें।

इससे हर किसी को लाभ पहुंचा। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। हम आगे भी स्थानीय विक्रेताओं से ही सामान खरीदें, क्योंकि स्थानीय विक्रेताओं ने जहां लाकडाउन में देश को सशक्ति करने में अहम योगदान निभाया वहीं विदेशी कंपनियों का योगदान बिल्कुल न के बराबर था। सम्मेलन में

प्रदेश संयोजक विकास चौधरी ने आये सभी लोगों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम का संयोजन पूर्वी विभाग के प्रमुख कार्यकर्ता सुंदर चौधरी व दिनेश बघेल द्वारा किया गया।

https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-kavi-sammelan-of-swadeshi-jagran-manch-on-holi-22554801.html

रोजगार और स्वरोजगार युक्त भारत के लिए कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से 'स्वावलंबी भारत' अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी के आईटीओ स्थित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आरएसएस 11 संगठनों के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक देशव्यापी अभियान चला रहा है, जिसे 'स्वावलंबी भारत' नाम दिया गया है।

इस अभियान के तहत शनिवार (9 अप्रैल 2022) को मजदूर संघ के कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में संघ के 11 संगठनों स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, लघु उद्योग भारती, ग्राहक पंचायत, सहकार भारती, एबीवीपी, भाजपा, सेवा भारती, वीएचपी और वनवासी कल्याण आश्रम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वावलंबी भारत अभियान के दिल्ली प्रांत समन्वयक सत्यवान गर्ग ने बताया कि इस अभियान को स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में इस अभियान को गति देने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें तीन सत्र हुए।

पहले सत्र में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने अपने संबोधन में बताया कि कैसे अमेजॉन और वॉलमार्ट जैसी विदेशी कंपनियां देश का रोजगार खत्म कर देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरे सत्र में सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी–अपनी राय और अनुभव साझा किए, जबकि तीसरे सत्र में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंगठक श्री सतीश कुमार ने अभियान पर आगामी योजना के बारे में चर्चा की।

गर्ग ने बताया कि इस अभियान के तीन मुख्य उद्देश्य हैं।

पहला भारत में कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे न हो, दूसरा भारत शत प्रतिशत रोजगार एवं स्वरोजगार युक्त हो और तीसरा भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक 10,000 अरब डॉलर हो।

कार्यशाला में अभियान के सह समन्वयक वीरेंदर नागपाल, दिल्ली की महिला समन्वयक डॉ. सुनीता दहिया, कार्यालय प्रमुख हिमालय, स्वदेशी जागरण मंच के दिल्ली प्रांत प्रचार प्रमुख जसप्रीत सिंह और अन्य लोग उपस्थित रहे।

स्वावलंबी भारत अभियान की प्रांतीय कार्यशाला आयोजित

स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा भारत वूमेन बीएड महाविद्यालय डिगाडी कल्ला जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आर्थिक विषयों के 11 संगठन के समवन्य से स्वावलंबी भारत अभियान की प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मुख्य वक्ता के रूप में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल ने कहा की कोरोना काल के पश्चात प्रत्यक भारतीय को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूरे भारत वर्ष में स्वावलंबी भारत अभियान की मुहिम चलाई जा रही है। संघ में भारत में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए प्रथम बार अपनी राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा में आर्थिक विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 200 वर्षों से भारतीय लोगों की मानसिकता लॉर्ड मैकाले की नीतियों के कारण स्वरोजगारपरक न होकर नौकरी प्राप्त करने की रही है। आज हमें इस मानसिकता को परिवर्तित करने की जरूरत है तभी हम 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकेंगे और भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में ऐसे परिदृश्य बनाने की आवश्कता है कि आज का युवा स्वयं अपना रोजगार बिना किसी बाधा के शुरू कर सके और भारत सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। यूक्रेन और रूस के युद्ध और कोरोना काल के बाद यह पहली आवश्कता हो गई है कि हम पूर्णरूप से आत्मनिर्भर बनें। भारत के 1100 विश्वविद्यालय और 53000 महाविद्यालय में आए सभी छात्रों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है।

जोधपुर के वरिष्ठ उद्योगपति और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर राधेश्याम रंगा ने कहा कि हम यदि लगातार निष्काम भाव से प्रत्यनशील रहते है तो अवश्य ही हमे सफलता मिलती है और समाज उद्यमशील बनता है।

राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि हमारे समाज में कई उदाहरण है जिन्होंने जमीन से शुरुआत कर ऊंचाई को छुआ है और उन्होंने समाज को अपने अनुभव से एक दिशा दी है। स्वावलंबी भारत अभियान निश्चित ही देश को स्वरोजगार प्राप्ति की और ले जायेगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख श्याम मनोहर ने कहा कि स्वावलंब भारत अभियान को धरातल पर लाने के लिए जिला स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। जिले के विश्व विद्यालय, महाविद्यालय को जोड़कर इस अभियान को सफल बना सकते है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओ को भी इसमें भागीदारी निभानी पड़ेगी।

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में लघु उद्योग भारती के प्रांत अध्यक्ष रामानंद काबरा ने कहा कि सृजनशील लोगों की नई सोच ने पूरे विश्व में नए–नए क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया है। हमें भी अपने युवाओं को चिंतनशील बनाने की आवश्यकता है जो कि नए सोच को विकसित करके हम भारत को नए युग में ला सकते है। नौकरियों से देश नहीं बनता है। देश को बनाने के लिए स्वरोजगार की आवश्यकता होती है।

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख डॉ धर्मेंद्र दुबे ने कहा कि हम सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से भी युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सकते है और देश को आत्मनिर्भर बना सकते है।

स्वदेशी जागरण मंच के कृषि प्रकोष्ठ प्रमुख भागीरथ चौधरी ने पश्चिम राजस्थान के संदर्भ में स्वरोजगार उद्योगों के विषय में संबोधित किया।

मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉ सतीश आचार्य ने स्वावलंबी भारत अभियान के बारे में विस्तार से बताया कि किस प्रकार से इस अभियान को लोगों तक पहुंचाना है। इस कार्यशाला को अतुल भंसाली, भारतीय किसान संघ से तुलसाराम सेवर, ग्राहक पंचायत से धर्मेंद्र सोनी, लघु उद्योग भारती से अनिल अग्रवाल, मंजू सारस्वत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से डॉ. बलवीर चौधरी ने भी संबोधित किया।

इस कार्यशाला का संचालन प्रमोद पालीवाल ने किया और धन्यवाद का ज्ञापन पूर्व जिला प्रमुख पुनाराम चौधरी ने दिया। इस कार्यशाला में जोधपुर, फलोदी, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों से प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। ❑❑

स्वावलंबी भारत अभियान – कार्यशालाएं

सचित्र झलक

सेपाहीजाला, त्रिपुरा (मार्च 20, 2022)

मणिपुर (मार्च 28, 2022)

जोधपुर, (अप्रैल 03, 2022)

अहमदाबाद, गुजरात (मार्च 26, 2022)

'होली मंगल मिलन', दिल्ली (मार्च 17, 2022)

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 अप्रैल 2022
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान – कार्यशालाएं

सचित्र झलक

जबलपुर, महाकौशल (मार्च 5, 2022)

लुधियाना, पंजाब

सिलिगुड़ी, उत्तरी बंगाल (मार्च 25, 2022)

असम

दिल्ली (अप्रैल 09, 2022)

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती